twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शुक्रवार, 11 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 235, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का हल्लाबोल

7 शहरों में ट्रेनें रोकीं, 12 नेशनल हाईवे जाम; ईसी ऑफिस नहीं पहुंच सके राहुल-तेजस्वी

पटना/एजेंसी

राहुल गांधी को पटना में महागठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। यहां राहुल ने आरोप लगाया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा- इलेक्शन कमिश्नर भाजपा और संघ नेताओं की तरह बात करते हैं। उन्हें (भाजपा) पता चल गया है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, वे अब बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। राहुल ने कहा- आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा। कानून आपको नहीं छोड़ेंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कितने ही बड़े क्यों न हो कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आप अपना काम नहीं कर रहे हो।

राहुल बोले- विधानसभा चुनाव में 10% वोटर बढ़े

राहुल ने कहा, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ। उसके कुछ महीने बाद महाराष्ट्र और हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया ने जीत दर्ज की। कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव में हार गई। उस समय हमने ज्यादा कुछ बोला नहीं। कुछ समय बाद हमने

डेटा देखना शुरू किया। हमने पाया कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए वोटर्स जुड़े। मतलब विधानसभा चुनाव में 10% ज्यादा वोटर्स ने वोट किया। जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, कौन हैं, तो आश्चर्य की चीजें निकली। जिन-जिन सीटों पर वोटर्स बढ़े, वहां भाजपा जीती। सारे के सारे नए वोट भाजपा को गए।

जब हमने वोटर लिस्ट और वोटिंग की वीडियो मांगी तो इलेक्शन कमीशन शांत हो गया। एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं कई बार कहा। उन्हें बताया कि कानून के मुताबिक, हमें वोटर्स लिस्ट दी जाए। कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। वीडियो देने का कानून बदल दिया। कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर वोटर लिस्ट मांगी थी कांग्रेस ने 25 जून को महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर एउ को लेटर लिखा था। पार्टी ने आयोग से एक हफ्ते में महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल वोटर्स लिस्ट मांगी थी। साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग के वीडियो देने को कहा था।

कांग्रेस ने कहा था कि यह पुरानी मांग है और ईसी आसानी से दे सकता है। डेटा मिलने पर हम एनालिसिस करेंगे और ईसी से चर्चा करेंगे। इससे पहले 12 जून को एउ ने राहुल को लेटर लिखकर चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने आयोग को लेटर लिखा।

बंद के दौरान बिहार के 17 रेलवे स्टेशनों पर किया गया प्रदर्शन

राज्य के 17 रेलवे स्टेशनों पर भी बंद के दौरान प्रदर्शन किया गया। पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे) ने बुधावर को इसकी जानकारी दी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर के 17 अलग-अलग स्टेशनों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोका गया। हालांकि, इस दौरान कहीं भी हिंसा या तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोका गया। मजदूर एवं कर्मचारी संगठनों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर को बिहार समेत देश भर में बंद बुलाया। बिहार ग्रामीण बैंक में हड़ताल से करीब 10 हजार करोड़ रुपये के कारोबार के नुकसान होने की खबर है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले से तय कार्यक्रम के तहत इस बिहार बंद को धार देने के लिए पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद राहुल गांधी आयकर गोलंबर पर पहुंचे। जहां पहले से ही बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। यहां महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। आयकर गोलंबर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी सहित

महागठबंधन के अन्य नेता एक वाहन पर सवार होकर मार्च के लिए निकले। गाड़ी पर दिग्गज नेताओं के साथ पटना की सड़क पर कार्यकर्ता लगातार पैदल मार्च कर रहे थे। पैदल मार्च करते हुए यह हुजूम शहीद स्मारक पहुंचा। यहां निर्वाचन कार्यालय से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। कई कार्यकताओं ने यहां बैरिकेडिंग को तोडने.का भी प्रयास किया औ? कई बार स्थिति तनावपूर्ण भी बनी। पुलिस लगातार बैरिकेडिंग ना तोड़ने की अपील यहां कर रही थी। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार को घेरा तथा बिहार चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को घातक बताया।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर तंज

बिहार बंद के समर्थन में राहुल गांधी के पटना आने पर राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल पिकनिक मनाने बिहार आए हैं। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना-देना नहीं है।

सांसद अरुण भारती ने महागठबंधन पर साधा निशाना

चिराग पासवान के जीजा और लोजपा (रामविलास) के जमुई से सांसद अरुण भारती ने भी बिहार बंद को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "लोकतंत्र में विरोध, प्रदर्शन और हड़ताल करना सबका अधिकार है। मगर महाठगबंधन का 'बिहार बंद' और 'चक्का जाम' का असली मकसद है अपनी कुर्सी का इंतजाम।"

आईएमओ की बैठक में भारत ने उठाया कंटेनर शिप सुरक्षा और लैंगिक समानता का मुद्दा

लंदन/एजेंसी

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चल रही अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की परिषद के 134वें सत्र में भारत ने समुद्री सुरक्षा और लैंगिक समावेशिता जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। भारत के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अहम बैठक में हिस्सा लिया और कई जरूरी पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया। सत्र के पहले दिन भारत ने हाल ही में भारतीय जलक्षेत्र में विदेशी ध्वज वाले कंटेनर जहाजों से जुड़ी समुद्री घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। इन घटनाओं में अघोषित खतरनाक सामान और जहाजों की संरचनात्मक कमजोरियों के चलते सुरक्षा संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। भारत ने आईएमओ से मांग की कि इन घटनाओं की गहराई से जांच की जाए और कंटेनर शिपिंग के सुरक्षा ढांचे में जल्द सुधार किए जाएं। साथ ही लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक माल की पैकेजिंग, घोषणा और निगरानी के लिए सख्त अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने पर जोर दिया।

इस मौके पर भारत ने समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। भारत ने आईएमओ से अपील की कि वह इस तरह की घटनाओं की गहन वैश्विक समीक्षा शुरू करे ताकि भविष्य में समुद्री सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही भारत ने लैंगिक को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। आईएमओ की लैंगिक समावेशन रणनीति के तहत भारत ने 'सागर में सम्मान' नामक अपनी राष्ट्रीय पहल का जिक्र किया, जिसे 25 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिकाओं में भी अवसर देना है। भारत ने गर्व के साथ बताया कि देश में महिला नाविकों की संख्या में 650 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह आईएमओ के समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक समुद्री समुदाय के समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता रहेगा।

कृषि मंत्रालय ने सात नए उत्पादों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की दी स्वीकृति

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ौर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के साथ ही कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सात नए उत्पादों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है। इसका मकसद कृषि उत्पादों का कवरेज बढ़ाना और किसानों और व्यापारियों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाभ उठाने के अधिक अवसर प्रदान करना है। इन सात उत्पादों में गन्ना, मर्चा चावल, कतरनी चावल, जदार्लू आम, शाही लीची, मगही पान और बनारसी पान शामिल हैं। इन सात उत्पादों सहित ई-नाम प्लेटफॉर्म पर

उत्पादों की संख्या बढ़कर अब 238 हो गई हैं। को कृषि मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) ने 7 अतिरिक्त कृषि उत्पादों के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं। ये नए उत्पाद मापदंड राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय-विशेषज्ञों और एसएफएसी सहित प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाती है, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुविधाजनक बनाती है और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देती है। व्यापार योग्य मापदंडों का निर्माण प्रत्येक उत्पाद के लिए श्रेणी या रेंज प्रदान करता है और उपज की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।

ई-नाम पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिससे कृषि उत्पादों के डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लेटफॉर्म की क्षमता और सुदृढ़ होगी।

सीएम धामी मंत्रिमंडल ने दी जियो थर्मल एनर्जी नीति और खनिज नियमावली को मंजूरी

देहरादून/एजेंसी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग नहीं हुई। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी नीति, पुलों की क्षमता बढ़ाने, विजिलेंस विभाग में नये पदों को बढ़ाने, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से करने और खनिज सहित कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग के तहत पुलों की वहन

क्षमता बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू) के गठन की सहमति पर निर्णय लिया गया है। विजिलेंस विभाग में 20 नये पदो के लिए स्वीकृति मिली है। अब पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सूचीबद्ध सात कम्पनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए राज्य में भी सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना किया जाएगा।

राज्य कर विभागान्तर्गत डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य सूचना एवं साक्ष्यों का कलेक्शन, रिट्रीवल एवं एनालिसिस करते हुए कराधान के कानूनों का प्रभावी अनुपालन किया जाना है।

मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर, नदियां आयीं उफान पर

35 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में 12 जुलाई तक तेज बारिश का रहेगा दौर

भोपाल/एजेंसी

मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर बाढ़ के हालात बन गए है। तेज बारिश से प्रदेश के मंडला, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इससे कई रास्ते बंद हैं। नरसिंहपुर के कई गांव पानी में आधे डूब गए। प्रदेश में अब तक औसत 14 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 74% ज्यादा है। मौसम विभाग ने आज को भी प्रदेश के 35 जिलों में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्व हिस्से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में अति भारी बारिश का अनुमान है।

मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में दो ट्रफ का असर है। वहीं, साइक्लोनिक सकुर्लेशन सिस्टम भी एक्टिव है। इन वजहों से अति भारी या भारी बारिश हो रही है। लो प्रेशर एरिया (कम दबाव का क्षेत्र) की एक्टिविटी अगले कुछ दिन में देखने को मिलेगी। इससे बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले चार दिन यानी 12 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में तेज बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी हिस्से में सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने को विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम, जंगलों से मिले हथियार

चंडीगढ़/एजेंसी

पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी संगठन बाबर खालसा इंटरनेशनल की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने गुरदासपुर के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथियों तक पहुंचाए

जाने थे। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने को बताया कि बरामद सामान में दो एके-47 राइफल, 16 जिंदा कारतूस, दो मैगजीन और दो हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। शुरूआती जांच में पता चला है कि यह हथियार पाकिस्तान की एजेंसियों और रिंदा ने पंजाब में अशांति फैलाने के इरादे से भेजे थे। पुलिस की यह कार्रवाई एक बड़े हमले को टालने में सफल रही है। गुरदासपुर के पुराने शाला थाना क्षेत्र में जंगलों से बरामद की गई इस हथियारों की खेप को लेकर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट का फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली/एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कन्हैया लाल हत्या मामले के एक आरोपित मोहम्मद जावेद को तत्काल कोई भी राहत देने से भी इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मावकाश के बाद 14 जुलाई से शुरू हो रही है। आप उस समय जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बीच फिल्म को रिलीज किया जाए। ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है।

इसका ट्रेलर 4 जुलाई को रिलीज किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म में केवल एक पक्ष के हिस्से को ही दिखाया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे जिलाधिकारी: मुख्यमंत्री

देहरादून/एजेंसी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रति प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में जिलाधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी बनाते हुए, उन्हें संबंधित शिकायतों का निस्तारण करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को प्रभावी ठंग से अमल में लाया जाए। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों व माता-पिता

को उनके बच्चों, बालिग पोते-पोतियों अथवा संपत्ति के उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की वैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है।

इस कानून को अमल में लाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर कुल 13 अपीलीय भरण-पोषण अधिकरण व सब डिविजन स्तर पर 69 से अधिक भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं। जहां भरण-पोषण की राशि अधिकतम 10,000 प्रति माह निर्धारित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं, इसलिए उन पर इस कानून को सख्ती से अमल में लाते हुए, वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। साथ ही तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी भरण पोषण संबंधित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन भरण-पोषण अधिकारी के रूप में जिम्मेदार बनाए गए हैं।

संपत्ति हस्तांतरण में सुरक्षा प्रावधान

कानून के तहत यदि कोई वरिष्ठ नागरिक देखभाल की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित करता है, लेकिन इसके बाद तय शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो अधिकरण उस हस्तांतरण को अमान्य घोषित करते हुए, संपत्ति की वापसी सुनिश्चित कर सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं

बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी जिलों में निःशुल्क वृद्ध एवं निशक्तजन आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं। जहां कई जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक निवासरत हैं। राज्य में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का गठन करते हुए रामचंद्र गौड़ को अध्यक्ष और शांति मेहरा, नवीन वर्मा, व हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

धर्मांतरण मामले के आरोपित छांगुर बाबा की कोठी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

एजेंसी

बलरामपुर। अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपित गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को जिला एवं पुलिस प्रशासन ने छांगुर बाबा की बनी कोठी के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिशा है। सुरक्षा की लिहाज से कोठी और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उतरौला तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने बताया कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मधूपुर स्थित कोठी जो महिला मित्र नीतू उर्फ नसरिन के नाम पर है। करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से 3 बीघा में बनी यह कोठी धर्मांतरण नेटवर्क का अड्डा बनी हुई थी, जिसका खुलासा हाल ही में हुआ है। प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई सोमवार को कोठी के मुख्य गेट पर

उल्लेखनीय है कि एटीएस ने शनिवार को 50 हजार रुपये के इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरिन को गिरफ्तार किया था।

नोटिस चस्पा किया था। मंगलवार की सुबह प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल बुलडोजर लेकर छांगुर बाबा की कोठी पर पहुंची। इस मौके पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल भी मौजूद रहे। छांगुर बाबा की इस कोठी पर ताला लगा था, लेकिन अधिकारियों की निगरानी में मुख्य गेट का ताला तोड़कर टीम कोठी के अंदर पहुंची और सभी कमरों की तलाशी ली। इसके बाद कोठी के अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि एटीएस ने शनिवार को 50 हजार रुपये के इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरिन को गिरफ्तार किया था। दन दोनों पर अवैध रूप से धर्मांतरण का नेटवर्क संचालित करने का आरोप है। जांच के दौरान इस गिरोह के अलग-अलग संस्थाओं के नाम पर खुलवाए गये 40 बैंक खातों में सौ करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग की बात सामने आयी है। इस गिरोह के सदस्य 40 देशों की यात्रा कर चुके हैं। बाहर से युवक–युवतियां आकर उसकी कोठी में ठहरते थे। आरोप है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण कराने वाले को लोगों को पैसा भी देता था। गिरोह के सदस्यों को हर धर्म की लड़कियों का धर्मांतरण के लिए लाखों रुपये दिए जाते थे। विदेशी फंडिंग के मामले में ईडी भी जांच कर सकती है।

ट्रेन की चपेट में आई स्कूली वैन, दो छात्रों समेत तीन की मौत, मुआवजे का ऐलान

एजेंसी

चेन्नई। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के सेम्मनकुप्पम में मंगलवार सुबह एक स्कूल वैन के ट्रेन की चपेट में आने से दो छात्रों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में छह छात्र समेत सात लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार, यह हादसा सुबह 7:45 बजे हुआ। स्कूली वैन रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, तभी विलुप्पुरम-मयिलादुथुराई पैसेंजर ट्रेन ने वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वैन चालक और छह छात्र घायल हुए हैं,

जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायल छात्रों को कुड्डालोर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दुर्घटना में निमिलेश (12) और डी. चारुमति (16) नाम के दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि 55 वर्षीय अन्नादुरई नाम के एक व्यक्ति की टूटे हुए बिजली के तार के संपर्क में आने से मौत हो गई। हादसे की रेलवे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं दुर्घटना में दो छात्रों की मृत्यु की दुखद खबर से स्तब्ध और दुखी हूं। मैं मृतक छात्रों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

एनआरसी नोटिस पर ममता का आरोप-बंगाल के लोगों की पहचान मिटाने की साजिश

कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल द्वारा कूचबिहार निवासी उत्तम कुमार ब्रजवासी को भेजे गए एनआरसी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला करार देते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कूचबिहार के दिनहाटा इलाके के रहने वाले उत्तम कुमार ब्रजवासी पिछले 50 वर्षों से बंगाल में रह रहे हैं, उन्हें असम की एनआरसी ट्राइब्यूनल से विदेशी/अवैध प्रवासी होने के शक में नोटिस भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तम कुमार के पास सभी वैध पहचान-पत्र मौजूद होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो पूरी तरह असंवैधानिक और अमानवीय है। अपने एक्स पोस्ट में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अकेली घटना नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा बंगाल में एनआरसी थोपने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। ममता ने इसे हाशिये पर खड़े समुदायों को डराने और उन्हें वोट के अधिकार से वंचित करने का सुनियोजित प्रयास बताया। मुख्यमंत्री ने सभी विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि इसके खिलाफ सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकसाथ आकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय संविधान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो बंगाल कभी चुप नहीं बैठेगा।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पितृ शोक

जोधपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाउलाल वैष्णव का मंगलवार को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार थे और उनका एम्स चिकित्सालय जोधपुर में इलाज चल रहा था। उनके निधन की सूचना पर परिजन रातानाडा स्थित आवास पर एकत्र होना शुरू हो गए हैं। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता 81 वर्षीय दाउलाल वैष्णव काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिता के अस्वस्थ होने पर पहले भी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर आए थे। यहां एम्स में उनका उपचार चल रहा था। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को हालत अत्यंत नाजुक होने के कारण

तत्काल प्रभाव से जोधपुर पहुंचे और अंतिम सांस लेने तक उनके साथ रहे। उनके पिता दाउलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार जोधपुर के कागा श्मशान स्थल पर किया जाएगा। पार्थिव देह को रातानाडा स्थित आवास पर लाया गया है। परिवार की ओर से बताया गया है कि दाउलाल के अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह दोपहर बाद 3.00 बजे से सी-17, महावीर कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर में रखी जाएगी। इसके बाद सायं 4.30 से उनकी अंतिम यात्रा का प्रस्थान कागा स्वर्गाश्रम श्मशान घाट, नागौरी गेट जोधपुर के लिए होगा, जहां उनका अंतिमसंस्कार किया जाएगा। दाउलाल वैष्णव मूलतः पाली जिले के जीवंद कला निवासी थे और बाद में परिवार के साथ जोधपुर में बस गए थे।

असम के कार्बी आंगलोंग में 4.1 तीव्रता का भूकंप

गुवाहाटी। असम के कार्बी आंगलोंग और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह 09 बजकर 22 मिनट 19 सेकेंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गयी। भूकंप में किसी के हताहत होने या अन्य नुकसान की खबर नहीं है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र कार्बी आंगलोंग जिले में सतह से 25 किलोमीटर नीचे 26.51 डिग्री उत्तर और 93.15 डिग्री पूर्व अक्षांश पर स्थित था। भूकंप के झटके राज्य के पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग और आसपास के इलाकों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य नगालैंड के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किए गए।

छांगुर बाबा पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन, कहा- ऐसी सजा देंगे, जो समाज के लिए एक उदाहरण बने

एजेंसी

लखनऊ । धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। सीएम योगी का रिएक्शन ऐसे समय में आया है जब बलरामपुर में जलालुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सीएम योगी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सरकार बहन-बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां

समाज विरोधी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उन्होंने आगे लिखा,उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी, जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। बता दें कि यूपी एटीएस ने एक संगठित धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए खुद को सूफी संत बताने वाले छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरोह पर विदेशी फंडिंग, करोड़ों की संपत्ति खरीद, प्रेमजाल और प्रलोभन के जरिए सैकड़ों लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ अमिताभ यश ने बताया था कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन खुद को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है। जानकारी मिली थी कि वह बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। इसकी जांच एसटीएफ ने की। ग्रुप के एजेंट युवाओं को प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिगों का भी धर्मांतरण गैंग द्वारा करवाया गया। इनके 40 खातों में विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया।

अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना, कहा- भाजपा जाए, तो कानून-व्यवस्था आए

एजेंसी

लखनऊ । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जाए, तो कानून-व्यवस्था आए। दरअसल, यूपी के कन्नौज में एक गांव में कुछ मकानों में चोरी हो गई है। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। एडिशनल एसपी ने बताया कि कन्नौज के एक गांव में दो घरों में चोरी हो गई है, जिसका खुलासा करने के लिए टीम को अलर्ट किया गया है। जल्द ही पुलिस अभियुक्तों को पकड़ेगी। खया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में चौपट कानून-व्यवस्था का एक और समाचार : कन्नौज के ग्राम भुरजानी पोस्ट जसोदा में चोरों द्वारा 5 घरों में घुसकर लाखों रुपए की नगदी व जेवरात की चोरी। इन चोरियों का राज भी बंटवारे की लड़ाई से खुलेगा, पुलिस की कार्रवाई से नहीं। भाजपा जाए, तो कानून-व्यवस्था आए। जीरो हुआ जीरो टॉलरेंस। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस के कथित उत्पीड़न की शिकायत की है।

मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि अब इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। हम अफसरों से बात करेंगे। अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठाते हुए कहा, ÷मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के एक्सप्रेस-वे बनवा सकते हैं, लेकिन क्या कांवड़ यात्रियों के लिए 1000 करोड़ का कॉरिडोर नहीं बन सकते? हमारी सरकार आएगी तो श्रद्धालुओं के लिए समर्पित कांवड़ कॉरिडोर बनाएंगे।

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण

एजेंसी

पटना । बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में युवा आयोग के गठन सहित कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में युवा आयोग के गठन सहित कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों

पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में दिव्यांगजनों को लेकर भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार रुपये और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अंतर्गत न्यूट्री सीरियल्स (मिलेट्स) योजना के तहत खरीफ मौसम में मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई एवं कुल 46 करोड़ 75 लाख रुपये निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

नाले में उफान ने मचाई गांव में तबाही, उजड़े आशियाने, प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार

एजेंसी

मंडी । हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग गांव में एक छोटे नाले में अचानक उफान आने से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। घरों में इतना पानी और मलबा घुस चुका है कि वहां रहने लायक परिस्थितियां नहीं हैं। प्रभावित परिवार राहत शिविरों और रिश्तेदारों के घरों में शरण लेने को मजबूर हैं। इनके पास कुछ कपड़ों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। थुनाग बाजार के साथ लगते इस गांव में 30 जून की रात करीब 11:30 बजे से लेकर 12:00 बजे के बीच ऐसी तबाही शुरू हुई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों के अनुसार, यह नाला उस रात भारी बारिश के चलते उफान पर आ गया और कई पक्के मकान मलबे में तब्दील हो गए। आपदा का आलम यह रहा कि मलबा कई घरों की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। टूटी दीवारों के बीच फंसे विशाल पेड़ और भारी पत्थर यह साफ दर्शाते हैं कि बाढ़ ने किस तरह तबाही मचाई। कई परिवारों की जिंदगी भर की पूंजी कुछ ही मिनटों में मलबे में दफन हो गई।

आपदा प्रभावित स्थानीय निवासी नंदा देवी और कांता देवी ने बताया कि उनका पूरा परिवार दशकों पिछले 27 वर्षों से इसी गांव में रह रही हैं, ने बताया कि उनके पति किडनी रोग के मरीज हैं। बाढ़ के कारण रास्ते बंद हो गए थे, अब जाकर सड़क खुली है और आज उन्हें

से इस गांव में रह रहा था। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी अचानक नाले से तेज गर्जना की आवाजें आने लगीं और कुछ ही मिनटों में पानी और मलबा घर के भीतर घुस गया। हमें कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला, बस जान बचाकर भागे। आज हमारे पास तन ढकने के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा।वहीं, जमना देवी, जो इलाज के लिए जालंधर ले जाया गया है। हमारे लिए यह दोहरी मार है। हमारा घर उजड़ गया और बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज की चिंता अलग। इस आपदा में कुल 5 परिवारों के करीब 25 से 30 लोग पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। सभी प्रभावितों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें किसी सुरक्षित और स्थायी स्थान पर पुनर्वासित किया जाए।

भाजपा ने खड़गे पर लगाया राष्ट्रपति मुर्मू-पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अपमान का आरोप, बोले- माफी मांगे कांग्रेस

एजेंसी

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि खड़गे ने देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, यह दलित और आदिवासी समुदायों का अपमान है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। गौरव भाटिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का

जानबूझकर अपमान किया है। क्या यह वही कांग्रेस पार्टी है जो खुद को संविधान की रक्षक कहती है? जिस पार्टी के नेता हाथ में संविधान की प्रति लेकर जनता के सामने नारे लगाते हैं, वही नेता देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का इस तरह से अपमान करते हैं। इससे कांग्रेस की संकीर्ण, जातिवादी और संविधान विरोधी सोच उजागर होती है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह बयान आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता का घिनौना प्रदर्शन है। यह कांग्रेस की गिरी हुई राजनीतिक सोच का उदाहरण है। देश आज इन बयानों पर थू-थू कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में इतनी कटुता और नफरत क्यों भरी हुई है? क्या यह वहीं कांग्रेस है, जिसने दशकों तक सत्ता में रहते हुए वंचित वर्गों के अधिकारों की अनदेखी की? उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि असली भूमि हड़पने वालों का इतिहास कांग्रेस परिवार से जुड़ा है। जिस तथाकथित नकली गांधी परिवार से रॉबर्ट वाड्रा ताल्लुक रखते हैं, वही असल में जमीन कब्जाने का जीवंत उदाहरण है। आज जब एक गरीब, आदिवासी, मेहनतकश महिला देश की राष्ट्रपति बनी हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को यह रास नहीं आ रहा। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान है।

अमरनाथ यात्रा के लिए 7500 से अधिक तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना

एजेंसी

जम्मू। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 7,500 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था मंगलवार सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ नू। अधिकारियों ने बताया कि 38 दिवसीय तीर्थयात्रा 3 जुलाई को घाटी से दो मार्गों अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान-पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग से शुरू हुई थी। यात्रा 9 अगस्त को समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 94,000 से अधिक तीर्थयात्री श्री अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग (हिमलिंग) की पूजा-अर्चना कर चुके हैं।अधिकारियों ने बताया कि 5,516 पुरुषों और 1,765 महिलाओं समेत 7,541 तीर्थयात्रियों का सातवां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज तड़के 2.55 से 4.05 बजे के बीच भगवती नगर आधार शिविर से 309 वाहनों में सवार होकर कश्मीर स्थित दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ।

उन्होंने बताया कि पहला काफिला 148 वाहनों में 3,321 तीर्थयात्रियों को लेकर गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। इसके बाद 161 वाहनों में 4,220 तीर्थयात्रियों का दूसरा काफिला अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग से यात्रा कर रहा है।

हिंदी-मराठी विवाद पर बोले उदित नारायण, 'देश की सभी भाषाओं का हो सम्मान'

एजेंसी

मुंबई । महाराष्ट्र में उठे हिंदी और मराठी भाषा विवाद पर उदित नारायण ने संतुलित बयान दिया है। उन्होंने सबसे 'संस्कृति का सम्मान' करने की अपील की है। गायक ने इस मसले पर आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रहने के कारण स्थानीय भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि लोगों को भारत की अन्य भाषाओं की भी इज्जत करनी चाहिए। बातचीत में उदित नारायण ने कहा, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपको मराठी भाषा और वहां की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें भारत की दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना

चाहिए। उन्होंने कहा, हम महाराष्ट्र में रहते हैं और यह मेरी कर्मभूमि है, इसलिए यहां की भाषा खास है। इसके साथ ही, हमारे देश की सभी भाषाएं भी मराठी की तरह ही बराबर सम्मान की हकदार हैं। उदित से पहले इस मामले में कंगना रनौत ने भी अपनी राय पेश की थी। बात करते हुए उन्होंने देश की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना ने मराठी और हिमाचली लोगों की तुलना करते हुए कहा, महाराष्ट्र के लोग, खासकर मराठी लोग, बहुत प्यारे और सीधे-सादे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हिमाचली लोग हैं। कुछ लोग राजनीति में छा जाने के चक्कर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सनसनी फैलाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक देश के हिस्से हैं। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र, गुजरात, और दक्षिण भारत सभी जगह के लोग हिमाचल आते हैं। वे कितने भोले लोग होते हैं। हमें अपने देश की एकता को नहीं भूलना है।

नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपित गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली भारतीय मुद्रा छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस संबंध में गिरोह के दो सदस्यों अदनान और दानिश को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से कुल 44,500 की नकली भारतीय मुद्रा बरामद की गई है जोकि 100 और 200 के नोटों में थी। इसके अलावा रंगीन प्रिंटर, पेपर शीट्स, कटर और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक के अनुसार स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि दिल्ली और पश्चिम उप्र में 100 के नकली नोट चलन में लाए जा रहे हैं। जांच के दौरान पता चला कि उप्र के अमरोहा जिले में नकली नोट छापने की फैक्टरी संचालित हो रही है। सूचना को पुख्ता करने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने आरोपितों की पहचान अदनान और दानिश के रूप में की, जो अमरोहा के रहने वाले हैं। इस बीच पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपित अदनान नकली मुद्रा की एक खेप दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में डिलीवरी देने आएगा। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों 30,000 की नकली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया। अमरोहा में छापेमारी और दानिश की गिरफ्तारीअदनान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने अमरोहा में दानिश के घर पर छापा मारा। वहां से 14,500 की नकली मुद्रा, रंगीन प्रिंटर, पेपर शीट्स, कटर, और हरा टेप बरामद किया गया, जिसका उपयोग नोटों की छपाई में होता था।

द्वारका जिले में 29 अवैध विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया

नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस ने जून माह में विशेष अभियान चलाकर 29 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की है। यह सभी बिना वैध वीजा के भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें 18 बांग्लादेशी, 4 आइवरी कोस्ट, 3 नाइजीरिया, 2 लाइबेरिया, 1 तंजानिया और 1 बेनिन देश के नागरिक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार द्वारका जिले की ऑपरेशन यूनिट और थाना स्टाफ द्वारा नियमित रूप से ऐसे विदेशी नागरिकों की निगरानी की जाती है जो बिना वैध दस्तावेज़ों के देश में रह रहे हैं। इस क्रम में जून माह के दौरान विशेष अभियान चलाकर विभिन्न पुलिस टीमों ने इन्हें गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में स्पेशल स्टाफ द्वारा 11, थाना डाबरी द्वारा 07, एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा 06, थाना मोहन गार्डन द्वारा 03, एएटीएस द्वारा 01 और थाना उत्तम नगर द्वारा 01 विदेशी नागरिक पकड़ा गया है। इनमें एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल हैं जो बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 2.5 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है। द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी व्यक्तियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय एफआरआरओ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उनके डिपोर्टेशन का आदेश जारी किया गया।

मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली के समग्र विकास पर की चर्चा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के समग्र विकास के लिए ठोस, समयबद्ध एवं जनकेंद्रित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह जानकारी सीएमओ-दिल्ली ने एक्स पोस्ट में साझा की।बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने, जनहितकारी पहलों के विस्तार, डिजिटल सेवाओं के एकीकृत प्रसार और दिल्ली की सांस्कृतिक गरिमा के पुनर्निर्माण से जुड़े विविध पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई।

मंत्री प्रवेश साहिब ने प्रगति मैदान-भैरो मार्ग के अंडरपास-5 और नंद नगरी फ्लाईओवर का किया निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के साथ प्रगति मैदान-भैरो मार्ग पर बन रहे अंडरपास-5 और नंद नगरी फ्लाईओवर का निरीक्षण किया।मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने अंडरपास-5 साइट पर पत्रकारों से कहा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की फंडिंग से ये पूरा काम हो रहा है। 2023 में बाढ़ के कारण मिट्टी धंसने से काम रूक गया। बाढ़ का पानी इसमें दोबारा न आए इसके लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाए गए हैं। आवास और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। सरकार को जैसे ही आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी, इस परियोजना को आठ से नौ महीने में पूरा कर दिया जाएगा। इस काम को दिल्ली लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने मनोज तिवारी के साथ नंद नगरी फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार, फसलवार बनेगी कार्ययोजना

एजेंसी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों एवं फसलों के हिसाब से अलग-अलग अनुसंधान आधारित कार्ययोजनाएं बनाने की जरूरत पर बल दिया है तथा खराब गुणवत्ता के बीज और खाद की समस्या से निपटने के लिए जल्द ही कड़ा कानूनी प्रावधान लाने की बात कही है । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की 96वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर बल दिया। इस बैठक में केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के 18 से ज्यादा मंत्री उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि राज्यों का विषय है, राज्य सरकारों के सहयोग के बिना कृषि की उन्नति के प्रयास अधूरे हैं। केंद्र और राज्यों को मिलकर कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के आधार पर उनके

मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। एक समय था जब हमें निम्न गुणवत्ता वाला गेहूं अमेरिका से आयात करके खाना पड़ता था। भारत के बारे में यह छवि थी कि हम कभी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, लेकिन आज यह छवि और मिथक पूरी तरह से धूमिल हो गया है। खाद्यान्न के मामले में भारत रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अन्न के भंडार भर रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है। आज हम कृषि उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि हमारी उपलब्धियां अभिनंदनीय हैं। जिसके लिए सभी वैज्ञानिकों और आईसीएआर की टीम को बधाई दी, लेकिन उपलब्धियों के साथ-साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिस दिशा में भी हमें काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो सुझाव और मुद??दे उभर कर आएं हैं, उसी के आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य के हिसाब से भावी अनुसंधान के रास्ते तय करने होंगे। मांग आधारित अनुसंधान की जरूरत है। मात्र कागजी औपचारिकता के लिए अनुसंधान नहीं बल्कि किसानों की उपयोगिता को देखते हुए अनुसंधान किए जाने चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सोयाबीन, दलहन, तिलहन में अभी और अधिक शोध एवं काम की जरुरत है। गेहूं, चावल, मक्के के साथ-साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि को लेकर तेजी से प्रयास करने होंगे। इसके लिए राज्यवार एवं फसलवार कार्ययोजना बनाई जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का निरीक्षण किया तो वहां खराब बीज की गंभीर समस्या देखने को मिली। खराब बीज के कारण अकुंरण ही नहीं हो पाया था।

अंतरराज्यीय बैग चोर गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार, 12 बैग बरामद

एजेंसी

नई दिल्ली। रेलवे यूनिट ने एक सक्रिय अंतरराज्यीय बैग चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 चोरी के बैग, दो मोबाइल फोन और 47,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। गिरोह ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ वाले स्थानों को निशाना बनाता था। गिरोह के लोग विशेषकर काले और नीले रंग के बैग चोरी करते थे। जिससे सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचा जा सके। रेलवे के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के अनुसार 3 जुलाई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12477 (माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस) के कोच ए-1 से पांच बैग चोरी होने की सूचना मिली। इस पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में आरोपितों का सुराग पहाड़गंज स्थित क्रिस्टल होटल तक मिला। पुलिस टीम ने वहां छापेमारी कर तीन आरोपितों अमित कुमार (37), करन कुमार (27) और गौरव (33) को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने इनके चौथे साथी को आनंदविहार रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा। चौथे आरोपित की पहचान पुनीत महतो (38) के रूप में हुई। सभी आरोपित बिहार के रहने वाले हैं। डीसीपी के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि ये लोग रेलवे स्टेशन के पास होटल में कपड़ा व्यापारी बनकर रुकते थे।

यात्रा कर रहे यात्रियों के काले व नीले बैग चुराकर अपने मिलते-जुलते बैग में माल खाली कर देते और असली चोरी किए गए बैग को वापस स्टेशन लाकर छोड़ देते थे। इससे पुलिस और सीसीटीवी को चकमा देना आसान हो जाता था। बाद में ये बैग और अन्य सामान मार्केट में बेच देते थे। पकड़ से बचने के लिए ये लोग फर्जी नाम, सिम कार्ड और ठिकाने बदलते रहते थे।

दिल्ली भाजपा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन करेगी आयोजित

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर नाट्य प्रस्तुति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली भाजपा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर नाट्य मंचन प्रस्तुत करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारो को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पिछले एक महीने से दिल्ली भाजपा द्वारा तैयारी की जा रही है और मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में कमानी ऑडिटोरियम में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित नाटय मंचन का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा का हर कार्यकर्ता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारो को अनुसरण करता है। भाजपा विचार आधारित पार्टी है।

सचदेवा ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा सिर्फ ध्येय के लिए काम किया कभी पद के लिए काम नहीं किया। इसलिए उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वप्रथम के विचार से आगे बढ़ना उनका एक मात्र लक्ष्य था और आज उन्होंने जो बीज लगाया था वह भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक वटवृक्ष बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 8 जुलाई को शाम चार बजे होने वाले नाटय मंचन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े पहलु देखने को मिलेंगे।

बाल्या अवस्था में उनका स्वभाव, कॉलेज जीवन से लेकर युवा कुलपति बनने तक का सफर। राजनीतिक प्रवेश से लेकर देश की एकता के लिए नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और फिर जम्मू कश्मीर यात्रा और शेख अब्दुल्ला से मिलना है। इन सभी विषयों को दिखाने की कोशिश किया गया है। इसमें भाग लेने वाले कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं।

आईपी यूनिवर्सिटी में फार्मेसी प्रोग्राम की काउंसलिंग 9 जुलाई से

एजेंसी

नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपी यूनिवर्सिटी) में डी. फार्म, बी. फार्म तथा लेटरल एंट्री टू बी. फार्म प्रोग्राम की काउंसलिंग आगामी 9 जुलाई से शुरू हो रही है। यह काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में यूनिवर्सिटी के द्वारका स्थित मुख्य परिसर में आयोजित की जाएगी।

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि डी. फार्म प्रोग्राम की काउंसलिंग 9 जुलाई को होगी। वहीं बी. फार्म प्रोग्राम के लिए 9 और 10 जुलाई को तथा बी. फार्म में लेटरल एंट्री के लिए काउंसलिंग 11 जुलाई को निर्धारित की गई है। डी. फार्म में प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दिन विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम 60,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट तथा सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। बी. फार्म और लेटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए यह राशि 96,000 रुपये निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय

है कि ये तीनों फार्मेसी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के 'सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज' में संचालित किए जा रहे हैं, जो द्वारका कैंपस में स्थित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत जानकारी एवं दिशानिर्देशों के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.ipu.ac.in °ß´ www.ipu.admissions.nic.in पर विजिट करें।

ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने की देश के मुख्य न्यायाधीशों को आजीवन आवास देने की मांग

एजेंसी

नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व लोकसभा अध्यक्षों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को आजीवन सरकारी आवास देने के लिए विधायी प्रावधान किया जाए। प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एआईबीए के चेयरमैन डॉ. आदीश सी. अग्रवाल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को सेवानिवृत्ति के बाद उपयुक्त आवास न मिल पाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जज (संशोधन) नियम, 2022 के तहत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को छह महीने तक दिल्ली में किराया-मुक्त आवास का प्रावधान है, फिर भी डॉ. चंद्रचूड़ दिल्ली में उपयुक्त निजी आवास पाने में असफल रहे और उन्होंने अधिकृत

सरकारी आवास की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। सरकार ने सद्भावना के साथ यह विस्तार स्वीकृत किया, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को आधिकारिक सीजेआई बंगले में प्रवेश में विलंब हुआ। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई को कार्यभार संभाले एक महीने से अधिक हो चुका है, वे अभी तक अधिकृत आवास में प्रवेश नहीं कर सके हैं। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं एक व्यवस्थित और गरिमामयी समाधान की आवश्यकता को दर्शाती हैं। पत्र में कहा गया है, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में होता है, वैसे ही लोकतंत्र के तीनों स्तंभों- विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर सेवा देने वालों को आजीवन सरकारी आवास मिलना चाहिए। पत्र में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल का हवाला देते हुए बताया गया है कि अनेक न्यायाधीश बहुत कम अवधि के लिए पद पर रहे, कुछ तो केवल 29 या 36 दिनों के लिए, जो कि वरिष्ठता आधारित नियुक्ति प्रणाली का परिणाम है। अल्पकालिक कार्यकाल के बावजूद इन न्यायाधीशों पर संविधान की रक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। पत्र में यह भी इंगित किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पदों की तय अवधि होती है, जबकि मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल अनिश्चित और सीमित होता है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद स्थायित्व और गरिमा सुनिश्चित करने की एक प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।

हत्या की गुत्थी सुलझी, छह आरोपितों को पकड़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। रोहिणी जिले के विजय विहार थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है जबकि दो नाबालिग अपराधियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से मृतक का मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज भी बरामद किये हैं। पकड़े गए आरोपितों की पहचान विजय विहार निवासी करण उर्फ डोरेमोन, आकाश, सुमित, राहुल और दो नाबालिगों के रूप में हुई है। रोहिणी जिले के डीसीपी राजीव रजन के अनुसार 29 जून को पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) पर एक कॉल मिली। जिसमें विजय विहार स्थित महाराणा प्रताप पार्क में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि लगभग 25 वर्षीय युवक के हाथ सफेद गमछे से पीछे बंधे हुए थे और वह मृत अवस्था में था। जांच में मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी मनीष के रूप में हुई। विजय विहार थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि मृतक मनीष का सोनिया (परिवर्तित नाम) नाम की एक लड़की से प्रेम संबंध था। जब सोनिया को पता चला कि मनीष पहले से विवाहित है, तो उसने संबंध समाप्त कर दिया। मनीष दो दिन पहले ही दिल्ली आया था और सोनिया से मिलने की कोशिश कर रहा था। सोनिया द्वारा मना करने पर वह आहत था।

शताब्दी वर्ष में संघ का हिन्दू समाज के जागरण और सद्भाव निर्माण पर फोकस

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के कार्य विस्तार, शताब्दी वर्ष की तैयारी और विभिन्न प्रांतों में संघ कार्य स्थिति जैसे तीन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसमें मणिपुर में संघ की ओर से मैतई और कुकी समुदाय के बीच शांति बहाली के लिए किए जा रहे प्रयास भी शामिल हैं। बैठक में संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू समाज के जागरण एवं सद्भाव की कार्य दिशा भी तय की गई।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने केशव कुंज कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह बैठक कोई प्रस्ताव या निर्णय लेने के लिए नहीं थी, बल्कि संघ कार्य की दिशा तय करने पर केंद्रित थी। इस दौरान देश के विभिन्न प्रांतों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे संघ के सांगठनिक कार्यों की समीक्षा की गई। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि संघ दोनों समुदायों के साथ संवाद को आगे बढ़ा रहा है और कई सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। संघ का प्रयास शांति और सामाजिक समरसता के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रांत के संघचालक अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। केशव कुंज कार्यालय में 4 से 6 जुलाई तक

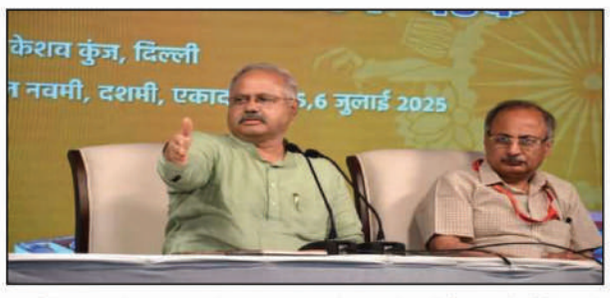

आयोजित अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में प्रांत प्रचारक और अखिल भारतीय कार्यकारणी के सदस्यों ने भाग लिया। आंबेकर ने पिछले दिनों आयोजित प्रशिक्षण वर्गों (संघ शिक्षा वर्गों) के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष कुल 21,879 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें 40 वर्ष से कम आयु के 17,609 और 40 वर्ष से ऊपर के 4,270 स्वयंसेवक शामिल हैं। देशभर के 8,812 स्थानों से इन वर्गों में भागीदारी हुई। केरल, तमिलनाडु, कश्मीर और वनवासी क्षेत्रों से भी उत्साहजनक भागीदारी देखी गई।शताब्दी वर्ष के चलते होने वाली संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मंडलों और शहरी क्षेत्रों में बस्तियों में समाज के प्रयासों से हिंदू सम्मेलन के आयोजन होंगे। 11,360 स्थानों पर सामाजिक सद्भाव निर्माण की गतिविधियां चलेंगी। यह खंड और नगर स्तर तक होंगी।

दिल्ली विस अध्यक्ष ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, नेवा समेत अन्य परियोजनाओं की दी जानकारी

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को दिल्ली विधानसभा में चल रहे कई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी प्रयासों की जानकारी दी। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी, जो नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विधानसभा परिसर को सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित करने की योजना के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि 500 किलोवाट की सोलर पावर परियोजना के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री को दिल्ली विधानसभा को एक सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल राजधानी की समृद्ध विधायी परंपरा को संरक्षित करेगी, बल्कि आधुनिक परिसर बनाने के साथ-साथ इसे जनभागीदारी, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक संवाद के एक जीवंत केंद्र के रूप में रूपांतरित करेगी।

मंत्री इंद्राज ने की नशामुक्ति अभियान की प्रगति पर समीक्षा बैठक

एजेंसी

नई दिल्ली। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने मध्य दिल्ली जिले में नशामुक्ति अभियान की प्रगति और रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मंत्री रविंद्र इंद्राज ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नशामुक्त दिल्ली का सपना तभी साकार होगा जब सभी विभाग, संस्थान और समाज आपसी समन्वय बनाकर इस दिशा में प्रयास करेंगे। बैठक में डीएम, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में समाज कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य दिल्ली के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएं। स्कूलों, कॉलेजों और शेल्टर होम्स में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने पुलिस, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के

बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पुनर्वास सेवाओं पर जोर देने के लिए कहा ताकि नशे की गिरफ्त से बाहर आने वाले नशे से दूर रहें। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि नशा पीड़ितों की काउंसलिंग, इलाज और पुनर्वास के लिए निजी संगठनों के अनुभव और संसाधनों का भी प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य न केवल नशे से जुड़े मामलों में कमी लाना है, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देना भी है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों से आग्रह किया गया है कि वे परिसर में नशा मुक्ति क्लब बनाएं और 'ड्रग फ्री कैम्पस' घोषित करें।

मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर क्षेत्र में जलापूर्ति संबंधी शिकायतों को दूर करने के दिए निर्देश

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवेज सिस्टम संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अभियांत्रिक अनुभाग के उच्च अधिकारियों के साथ अपने सरकारी आवास पर बैठक की। मंत्री ने बैठक में करावल नगर विधानसभा में पानी की नई पाइप लाइन बिछाने, पेयजल आपूर्ति की अनियमितताओं और प्रदूषित पानी की शिकायतों को दूर करने को लेकर अधिकारियों निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काली घटा रोड, वेस्ट करावल नगर, सादतपुर, दयालपुर में दूषित पानी की समस्या आ रही है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि काली घटा रोड पर एमसीडी द्वारा डीसिल्टिंग किए जाने की वजह से पानी प्रदूषित हुआ है और इसे दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं पाइप लाइन को शिफ्ट करने और उनकी मरम्मत करने का काम भी तेजी से हो रहा है और 10 दिनों के अंदर पाइप लाइन से गंदे पानी आने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को बताया की करावल नगर क्षेत्र की आबादी लगभग 5 लाख है और यहां पर पानी की मांग लगभग 25 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) है। मंत्री ने वर्तमान में पांच एमजीडी पानी की आपूर्ति के स्थान पर आठ एमजीडी पानी की आपूर्ति करने की भी बात कही। कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को बताया कि भगत सिंह कॉलोनी, अंकुर एन्क्लेव समेत कई ऐसे क्षेत्र जलापूर्ति का संकट है। उन्होंने कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे इलाके जहां सीवेज सिस्टम मौजूद नहीं हैं, वहां नई सीवेज लाइन डालने के कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री कपिल मिश्रा ने सोनिया विहार, श्रीराम कालोनी और राजीव नगर में नया सीवेज सिस्टम स्थापित करने के भी निर्देश दिए। ऐसे क्षेत्र जहां सीवर लाइन डाली जा चुकी है, लेकिन क्रियाशील नहीं हैं उन्हें भी क्रियाशील करने के निर्देश दिए। खजूरी खास, बिहारीपुर, तुकमीरपुर, दयालपुर, सादतपुर, वेस्ट करावल नगर, एसबीएस कॉलोनी, मुकुंद विहार, प्रकाश विहार, नई सभापुर गुजरान, अंकुर एन्क्लेव, वेस्ट कमल विहार और आसपास के ऐसे गांव जहां सीवर लाइन डाली जा चुकी है, लेकिन क्रियाशील नहीं है, उन इलाकों में सीवर लाइन की साफ सफाई कर उन्हें तत्काल क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवेज संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जा रहा है।

संपादक की कलम से

गुजरात मॉडल ढह गया!

बड़े जोर-शोर के साथ विकास का बहुप्रचारित गुजरात मॉडल दिन-ब-दिन ढह रहा है। पहलगाम से लेकर दिल्ली तक, यह ढहना जारी है, लेकिन इस मॉडल की कमजोरी गुजरात में ही सामने आई है। कल, भारत ने वडोदरा-आणंद को जोड़ने वाले पुल के ढहने की ह्यलाइवह्न तस्वीर देखी। इस पुल हादसे में ट्रक, टैंकर, कारें बह गईं और दस से ज्यादा लोग बह गए। मोरबी पुल से वडोदरा तक पुल का ढहना और बहना जारी है। मानो इतना ही काफी नहीं था, इसी बीच अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। २४३ लोग मारे गए। अब, जबकि गुजरात के सुपुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भ्रमण पर थे, तभी ह्यवडोदराह्न में पुल ढह गया। नरेंद्र मोदी कल तक इसी वडोदरा संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। अब वे वाराणसी से सांसद हैं। उस वाराणसी की सड़कों में भी ह्यकुएंह्न जितने गड्ढे हैं। मोदी ह्यगुजरात मॉडलह्न का सपना दिखाकर वाराणसी में जीते थे। इस सपने की धज्जियां खुद गुजरात में ही उड़ गईं। महिसागर नदी पर बना पुल ढह गया। इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि यह पुल पुराना था। अगर पुल पुराना था तो फिर इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? अगर यह बहुत पुराना था, तो नया पुल क्यों नहीं बनाया गया? क्या गुजरात मॉडल वाले यह नहीं समझते कि इस हादसे में निर्दोष लोग मारे गए? यह गुजरात सरकार की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। सरकार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राज्य का सबसे ऊंचा पुल दो टुकड़ों में टूटने जितना ह्यखतरनाकह्न हो गया था या फिर इस बात का अंदाजा होने के बावजूद लापरवाही

बरती गई। अगर अंदाजा होता, तो पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता। लेकिन चूंकि वहां की पूरी सरकार ह्यगुजरात मॉडलह्न के भरोसे पर चल रही थी, इसलिए यातायात जारी रहा और बुधवार को पुल के साथ यह भरोसा भी टूट गया। भले ही मान लिया जाए कि दुर्घटनाएं बोलकर नहीं होती, लेकिन यह तो एक तरह से पल्ला झाड़ना है। स्थानीय विधायक को अंदाजा था कि जो पुल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह पिछले कुछ सालों में कमजोर हो गया था और इस पर आवाजाही खतरनाक हो सकती है। इसके लिए एक नए पुल की मांग भी की गई थी। सरकार का कहना है कि उसने नए पुल के लिए २१२ करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर कर दिया है और एक सर्वेक्षण भी हो चुका है। तो अगर यह सब हुआ था, तो घोड़े कहां अटके थे? प्रधानमंत्री मोदी के ह्यगुजरात मॉडलह्न की अनगिनत ह्यपरिकथाएंह्न पिछले ढाई दशकों से रंगाकर सुनाई जाती रही हैं। बुधवार के पुल हादसे ने उन ह्यपरिकथाओंह्न के रंगों को एक बार फिर से कुरेद दिया। तीन साल पहले गुजरात के ही मोरबी में हुए भीषण पुल हादसे ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी थी। उस समय हुक्मरानों ने हादसे का ठीकरा पुल का रखरखाव और मरम्मत करने वाली कंपनी के माथे फोड़ दिया था और पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। मोरबी पुल हादसे में १४१ से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत

हो गई थी। वह पुल १४० साल पुराना था। अब ढहा हुआ गंभीरा पुल केवल ४५ साल पुराना था, लेकिन यह दो टुकड़ों में ढह गया। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया मोरबी हिलता पुल १४० साल तक चला। मोदी के तथाकथित गुजरात मॉडल द्वारा बनाया गया गंभीरा पुल के ४५ साल में ही दो टुकड़े हो गए! यह पाप केवल उन लोगों के लिए है जो गुजरात मॉडल के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। आपके २१२ करोड़ रुपए के प्रावधान और सर्वेक्षण का क्या फायदा? यदि गुजरात मॉडल दूसरों से अलग होता, तो यह कमजोर पुल ह्यप्रावधान और सर्वेक्षणह्न के कागजी घोड़े में नहीं फंसता और निर्दोष लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। वही सरकारी उदासीनता जिसके कारण पिछले महीने पुणे जिले में कुंडमाला पुल ढह गया, वही सरकारी उदासीनता है जिसके कारण तीन साल पहले गुजरात में मोरबी चल पुल दुर्घटना हुई और अब वडोदरा में गंभीरा पुल ढह गया। ह्यगुजरात मॉडलह्न के पांव भी मिट्टी के निकले। प. बंगाल में एक पुल गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने संभावना व्यक्त करते कहा था कि यह हादसा ह्यऐक्ट आफ प्रष्ठाडह्न है। तो बुधवार को उनके ही गुजरात में हुए पुल हादसे पर मोदी का क्या कहना है? क्या मोदी यह कहने की हिम्मत करेंगे कि यह भी ह्यऐक्ट ऑफ प्रष्ठॉडह्न है? मोदीजी, आपका गुजरात मॉडल भी गंभीरा पुल जितना ही कमजोर निकला है। अब तो मान लीजिए कि यह पुल नहीं, बल्कि गुजरात मॉडल ढहा है!

तौलिया-बनियान गैंग

महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं रहा है। फडणवीस सरकार का समर्थन करनेवाले विधायक संजय गायकवाड ने जिस तरह से विधायक निवास की कैंटीन के कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की, वह धक्कादायक है। विधायक गायकवाड ह्यपचास खोकेह्न वाले विधायक हैं। फिर भी वह विधायक निवास में रहते हैं। मंगलवार की रात, विधायक ने अपने कमरे में कैंटीन से दाल-भात और चपाती जैसा साधारण ह्यमेनूह्न ऑर्डर किया। उन्होंने महसूस किया कि यह भोजन विधायकों के खाने लायक नहीं था। इस कैंटीन में सुबह से सैकड़ों लोगों ने उस भोजन का स्वाद चखा होगा, लेकिन विधायक को यह पच नहीं पाया। उनका कहना था कि दाल खराब थी और बदबू आ रही थी। विधायक निवास की कैंटीन सरकारी सब्सिडी के कारण सस्ता भोजन प्रदान करती है और कई लोग इसका लाभ उठाते हैं। उनमें अन्य विधायक, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी भी हैं, लेकिन विधायकों की ह्यघ्राणेंद्रियह्न दूसरों की तुलना में तेज और जीभ तीखी होती होगी इसलिए कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है, इससे बदबू आती है कहते हुए विधायक महोदय गुस्से में बनियान और टॉवेल में ही कैंटीन में घुस गए। उन्होंने कैंटीन के गरीब-दुर्बल कर्मचारियों पर बेरहमी से हमला किया। उन पर लात-घूंसों से हमला किया, गालियां दीं। पचास खोकों की टॉनिक पिए विधायक के शक्तिशाली मुक्कों के सामने उन गरीब लोगों की क्या चलती? इस हाथापाई में विधायक की कमर में बंधा ढीला तौलिया खुल जाने की आशंका थी और महाराष्ट्र को एक अनचाहा नजारा देखना पड़ता। विधायक गायकवाड जिस तरह से गरीब कर्मचारियों को बॉक्सर की तरह मुक्के

मार रहे थे उसे देखते हुए एक मुक्का जानलेवा हो सकता था इसलिए विधायक गायकवाड पर हत्या का प्रयास, सार्वजनिक स्थान पर मारपीट, अपमान, गाली-गलौज, धमकी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था। कैंटीन पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या गृह मंत्री को इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था कि सत्ताधारी दल का विधायक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र वाले परिसर में एक कर्मचारी की हत्या की कोशिश कर रहा है? लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि, ह्ययह मारपीट ठीक नहीं है। यह सभापति के अधिकार क्षेत्र का मामला है। उन्हें ही फैसला लेना चाहिएह्न मुख्यमंत्री कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। क्या मौजूदा सभापति या अध्यक्ष मुख्यमंत्री से पूछे बिना फैसला ले सकते हैं? विधायकों की अयोग्यता के मामले में दबाव में फैसले लेनेवालों और दिल्ली से आए फैसले के कागज पढ़नेवालों से मुख्यमंत्री फैसले की उम्मीद करते हैं। जो अध्यक्ष विधानसभा में विपक्ष के नेता के मामले में फैसला लेने को तैयार नहीं हैं और अनाप-शनाप जवाब देकर समय काट रहे हैं, वे हंगामा करनेवाले विधायकों पर कार्रवाई कैसे करेंगे? विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को ह्यनजरानाह्न देने के लिए इकट्ठा की गई करोड़ों की रकम धुले के एक विश्राम गृह में जब्त कर ली गई। विधानसभा अध्यक्ष को इस पर भी फैसला लेना है। महाराष्ट्र की छवि खराब करनेवाले ये अपराध विधानमंडल में हुए और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इसे

आतंकवाद में डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग चिन्ताजनक

-ललित गर्ग-

टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की नई रिपोर्ट में आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा के समक्ष एक नई और गहन चुनौती की ओर संकेत करते हुए आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते प्रयोग को गहन चिन्ताजनक बताया है। रिपोर्ट में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और डार्कनेट जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और संचालन के बढ़ते खतरे पर न केवल प्रकाश डाला गया है बल्कि गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट ने आतंकवाद के एक अलग ही पहलू की ओर ध्यान खींचा है। इसमें बताया गया है कि टेक्नॉलजी तक आतंकी संगठनों की आसान पहुंच उन्हें और खतरनाक बना रही है। इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नई रणनीति एवं नियंत्रण नीति की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों में पलने-बढ़ने वाले आतंकी संगठन इन तकनीकों का उपयोग कर न केवल फंडिंग जुटा रहे हैं, बल्कि गोपनीयता और पहुँच के नए मार्ग भी तलाश रहे हैं। इसके अलावा, आतंकवादी संगठन अब विकेंद्रीकृत मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसेकि अल-कायदा क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर धन जुटाना और संचालन करना। भारत ने समय-समय पर पाकिस्तान पोषित एवं पल्लवित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए दुनिया से मिल रहे आर्थिक सहयोग पर चिन्ता जताई और कठोर कार्रवाई की मांग की, इस रिपोर्ट को भारत के रुख का समर्थन करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

एफएटीएफ के मुताबिक, 2019 में पुलवामा और 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमलों के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था और इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर एमेजन से खरीदा गया था। गोरखपुर में हुए हमले में पैसों के लेनदेन में ऑनलाइन जरिया अपनाया गया। गोरखपुर वाले केस में आतंकी विचारधारा से प्रभावित शख्स ने इंटरनैशनल थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन और वीपीएन सर्विस का उपयोग किया था। इस

तरह से उसने आईएसआईएल के समर्थन में विदेश में धन भेजा था और उसे भी बाहर से आर्थिक मदद मिली थी। वीपीएन एक डिजिटल तकनीक है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता की लोकेशन और पहचान को छुपाती है। जब कोई व्यक्ति वीपीएन का उपयोग करता है, तो उसका इंटरनेट ट्रैफिक एक एन्क्रिप्टेड सुरंग के माध्यम से किसी अन्य देश के सर्वर से होकर गुजरता है। इससे उसकी वास्तविक पहचान छिप जाती है और वह सेंसरशिप, ट्रैकिंग और जियो-रिस्ट्रिक्शन से बच सकता है।

2024 तक दुनिया में 150 करोड़ से अधिक वीपीएन यूजर्स हैं। इनमें से बड़ी संख्या एशिया और मध्य पूर्व से है, जहां सेंसरशिप या निगरानी से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में 12 से 14 करोड़ वीपीएन उपयोगकर्ता हैं। भारत वीपीएन यूजर्स की संख्या में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। वीपीएन का उपयोग कर आतंकी सोशल मीडिया और गुप्त चैनलों के जरिए युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने का काम करते हैं। कुछ आतंकवादी समूह वीपीएन नेटवर्क का प्रयोग कर सरकारी वेबसाइटों, रक्षा प्रतिष्ठानों और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला करते हैं। दुनिया की एक तिहाई आबादी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। इस साल ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट के 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत इस लिस्ट में फिलहाल सातवें नंबर पर है। लेकिन सवाल यह है कि इस डेटा के बीच अगर कुछ संदिग्ध लोग कुछ हजार डॉलर की खरीददारी करते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे जाकर किसी आतंकी हमले में होता है, तो उसे चिह्नित कैसे किया जाए? एफएटीएफ ने कुछ दिनों पहले पहलगाम को लेकर कहा था कि इतना बड़ा आतंकी हमला बाहरी आर्थिक मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। उसकी हालिया रिपोर्ट इसी बात को और पुष्ट कर देती है। आतंकियों ने अपने काम का तरीका बदल लिया है। वे इंटरनेट की दुनिया की ओट ले रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है।

एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूहों ने अब पारंपरिक धन स्रोतों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल वित्तीय माध्यमों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये माध्यम उन्हें सरकार की नजरों से बचाते हुए सीमाओं के पार फंडिंग जुटाने की सहूलियत देते हैं। साथ ही, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर वे अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर भले हो गया हो, लेकिन उसके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आई है। अनेक ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एफएटीएफ ऑब्जर्वेशन्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी गुटों को डिजिटल इकोसिस्टम का खुले तौर पर उपयोग करने दिया जा रहा है, या कभी-कभी सरकार की मौन सहमति से। उदाहरण के रूप में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल टोकन के जरिए फंड जुटाने की नई तरकीबें अपनाई हैं। कई मामलों में आतंकी फंडिंग के लिए फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक मीडिया अभियानों का सहारा लिया गया है। ह्यगजवा-ए-हिंदह्न जैसे डिजिटल प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी जमीन से संचालित होकर भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में लगे हैं।

भारत के विरुद्ध हाइब्रिड वारफेयर और साइबर जिहाद की रणनीति पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की नीति का हिस्सा बन चुकी है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां डिजिटल माध्यम से न केवल फंडिंग, बल्कि ब्रेनवॉशिंग और भर्ती का कार्य भी तेजी से हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जाता है। उत्तर पूर्व में उग्रवादी संगठनों को डिजिटल भुगतान और चैनलों के माध्यम से सहायता मिलती रही है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान समेत उन सभी देशों से अपेक्षा की है कि वे डिजिटल वित्तीय निगरानी तंत्र को मजबूत करें। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। आतंकी संगठनों के ऑनलाइन अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तकनीकी टूल्स विकसित करें। एफएटीएफ का चेतावनी के स्वरों में यह भी कहना है कि यदि आतंक के गढ़ एवं आतंकवाद को पोषित करने वाले इन देशों ने इन सिफारिशों पर अमल नहीं किया तो उन्हें ह्यहाई रिस्क जॉनह्न की सूची में डाला जा सकता है। भारत को इस डिजिटल आतंकी खतरे से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए-क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की रियल-टाइम निगरानी, साइबर आतंकवाद पर विशेष फोर्स का गठन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आतंकी कंटेंट की पहचान और हटाने के लिए मजबूत कानून, डार्क वेब और फेक डोनेशन चैनलों की सतत निगरानी आदि कदम उठाने चाहिए।

डिजिटल तकनीक ने जहां मानव जीवन को सरल और तेज किया है, वहीं इसका दुरुपयोग करके आतंकवाद को नया चेहरा देने की कोशिशें चिंता का विषय हैं। एफएटीएफ की चेतावनी को गंभीरता से लेने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होगा ताकि वे अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद एवं डिजिटल आतंकवाद के अड्डों को समाप्त करें। तभी एक सुरक्षित डिजिटल विश्व और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की कल्पना की जा सकती है। एफएटीएफ रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि आतंकवादियों ने अपने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए वैश्विक दर्शकों से धन जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर धन उगाहने वाले प्लेटफॉर्म और क्राउडफंडिंग माध्यमों से आतंकवाद के वित्तपोषण प्राप्त किया है। आतंकवादी संगठन पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल तरीकों से भी धन जुटाकर आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं। भारत ने एफएटीएफ रिपोर्ट को अपने रुख के समर्थन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यह रिपोर्ट आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट आतंकवाद के वित्तपोषण और संचालन में शामिल देशों और व्यक्तियों पर दबाव बढ़ाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायक हो सकती है।

कौन है ये बुड़बक डूबे?

देश में जब से मोदी युग की शुरूआत हुई है, तब से भाजपा में कई हलके बकवास लोगों को इज्जत मिलने लगी है। ह्यपतिव्रता के गले में पत्थर की माला और वेश्या के गले में मणियों की मालाह्न कुछ ऐसी स्थिति सभी क्षेत्रों में बन गई है। निशिकांत दुबे के गले में भी ऐसी ही मणियों की माला है। यह सज्जन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र और मराठी लोगों के खिलाफ उन्होंने विष वमन किया है। यह दुबे सज्जन कहते हैं, ह्यअब महाराष्ट्र में क्या बचा है? महाराष्ट्र का वैभव खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में कौन-सा बड़ा उद्योग है? तुम मराठी लोग हमारे धन पर जी रहे हो। यदि आप महाराष्ट्र से बाहर आओगे तो हम मराठी लोगों को पटक-पटककर मार डालेंगेह्न दुबे का यह बयान महाराष्ट्र का घोर अपमान है। दुबे मोदी-शाह के आशीर्वाद से ऐसे बयान देता है और क्योंकि उसे मोदी का अभय प्राप्त है इसलिए उसे अभय मिलता है। इस व्यक्ति ने यह कहकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ??की थी कि ह्यसुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता पैदा करना चाहता हैह्न, लेकिन क्योंकि मोदी का अभय प्राप्त है इसलिए वह वहां भी बच निकला। दुबे की फर्जी ह्यएमबीएह्न डिग्री का मामला चौंकानेवाला है। संसद के हलफनामे में उसने बताया कि वह एमबीए है। उसने शपथ लेकर कहा कि यह डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की है, लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही स्पष्ट कर दिया कि यह डिग्री बोगस है, जाली है तो इस आदमी को गिरफ्तार करके पूछताछ करनी चाहिए थी। संसद को धोखा देने के लिए इस दुबे की संसद की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन संसद को इतना बड़ा धोखा देने के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दुबे का बचाव किया, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी की सारी ह्यडिग्रियांह्न बोगस, जाली निकलीं। इसलिए यह पूरा मामला ह्यजैसा गुरु वैसा चेलाह्न वाला है। फिर, जब यह ह्यबोगसह्न दुबे शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के खिलाफ विष वमन कर रहा था, तब मुख्यमंत्री फडणवीस और उनका नामर्द वैष्ठबिनेट दुम दबाए बैठा था। अपनी आधी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए

दिल्लीश्वरों की गुलामी

अख्तियार करनेवाले फेकनाथ शिंदे और उसके चालीस चोर भी दुबे के ह्यमहाराष्ट्र के प्रति अपमानजनक बयानह्न के बाद से बिल में छिपे हुए हैं। भाजपा सरकार या महाराष्ट्र विधानसभा में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस दुबे को उसकी जगह दिखा सके, जो महाराष्ट्र का पानी दिखा सके। ऐसा लगता है जैसे यह कीड़ों का राज्य कीड़ों के लोगों के लिए चलाया जा रहा है। कोई लोफर निशिकांत दुबे दिल्ली में बैठकर मराठी लोगों का अपमान करता है और फडणवीस की वैष्ठबिनेट षंडों की तरह चुप रहती है। इसका राज यह है कि इस निशिकांत दुबे के असली आका मोदी और शाह हैं। इसके कारण आधी दाढ़ी पर हाथ फिरानेवालों की हालत पतली हो गई है। दुबे कहता है, ह्यमहाराष्ट्र एक कंगाल राज्य हैह्न पूरा देश जानता है कि इस देश में कंगाल या ह्यबीमारह्न राज्य कौन हैं और कौन किसी की दया पर जी रहा है। महाराष्ट्र ने कभी अपनी रईसी का ह्यप्रदर्शनह्न नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र ने कड़ी मेहनत से जो धन और प्रगति अर्जित की है, उससे कई लोगों को ईर्ष्या है। कई लोगों ने महाराष्ट्र की संपत्ति को लूटने की कोशिश की है। यही कारण है कि मराठी लोगों को उनके उचित अधिकारों से वंचित किया गया है। जब कोई मराठी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ने निकलता है तो दूसरे प्रांतों के कौवे ह्यकांव-कांवह्न करके मराठी व्यक्ति को प्रांतीयवादी ठहराने की कोशिश करते हैं। दूसरे सभी प्रांत अपनी भाषा, भूमि, अस्मिता के लिए लड़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब मराठी अस्मिता की आवाज उठती है तो कंगाल राज्यों के बुड़बक डूबे शिवाजी महाराज के राज्य के खिलाफ जहर उगलते हैं। फिर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जहर को बर्दाश्त करनेवाले और उस दुबे के खिलाफ विरोध का एक भी शब्द नहीं बोलनेवाले हुक्मरान महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठे हैं। आज महाराष्ट्र देश में जीएसटी के रूप में सबसे अधिक कर दे रहा है। अगर सभी हिंदी भाषी राज्यों को मिला दिया जाए तो भी जून २०२५ के लिए महाराष्ट्र का जीएसटी कर आंकड़ा (३०,५५३ करोड़ रुपए) इससे अधिक है। इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसकी दया पर जी रहा है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो की धमकी देने के लिए मुंबई को ही क्यों चुना? इन बुड़बकों को इसका गहन अध्ययन करना चाहिए।

भाजपा के नए धर्मगुरु

श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बैरिस्टर जिन्ना की जी हुजूरी कर रहे थे, तब महाराष्ट्र और मराठी लोग गुलामी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मुंबई के मिल मजदूर करो या मरो के जोश के साथ सड़कों पर उतर आए थे। महाराष्ट्र दलाली के जाल और प्रलोभन में नहीं फंसा। यह सरस्वती और शौर्य का उपासक है। हिमालय की रक्षा का कर्तव्य सादि का ही है मानने वाला यह महाराष्ट्र कभी भी व्यापारिक दृष्टिकोण से काम नहीं करता। इसीलिए महाराष्ट्र का आचार-विचार आज भी मशाल की तरह धधक रहा है। महाराष्ट्र ने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। जाति, धर्म और प्रांत की परवाह किए बिना भूखे लोगों को भोजन, पानी और आश्रय दिया। कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दीं और अपने लोगों को बाहर रखा, तब महाराष्ट्र ही इन सभी हिंदीभाषियों का पालनहार था। जब हिंदीभाषियों के शवों को लावारिस मानकर प्रयागराज की गंगा में फेंका जा रहा था, तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र में इन सभी लोगों की ममतापूर्वक देखभाल की। ??तब यह डूबे कहां था? यह वही डूबे है, जिसने पहलगाम हमले में २६ महिलाओं के सिंदूर पोंछ दिए जाने के बाद कश्मीर जाकर पुलिस सुरक्षा में शराब पार्टी की थी। पहलगाम में भारतीय महिलाओं के सिंदूर की सुरक्षा के लिए एक भी पुलिसकर्मी नहीं था, लेकिन मोदी-शाह ने डूबे की भव्य शराब पार्टी की सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को लगा रखा था। यह मजाक है कि यह डूबे महाराष्ट्र को पटककर मारने की बात करता है। निशिकांत डूबे ने महाराष्ट्र को पटककर मारने की जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है।

मोदी-शाह ने महाराष्ट्र के खिलाफ अपना जहर उगलने के लिए इस डूबे के थोबड़े को चुना। डूबे का थोबड़ा यानी चौखटा एक गटर है। इस गटर से सुप्रीम कोर्ट और पहलगाम के निर्दोष पीड़ितों के बारे में लगातार गंदगी निकलती रहती है। इस गटर को एक बार वर्ली का गटर दिखाना ही होगा। अगर डूबे जैसे लोगों ने राज्यों और भाषाओं के बीच टकराव पैदा करने की सुपारी ली है और दलाली की है तो महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों को उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों को डूबे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना ही चाहिए।

अमीरों का ही राज....गरीबों का कौन?

देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने रविवार को वही बात कही, जो मुख्य न्यायाधीश गवई ने चार दिन पहले कही थी। देश की संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में जमा है, जबकि बहुसंख्यक जनता दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, मुख्य न्यायाधीश ने इन शब्दों से आर्थिक प्रगति की पोल खोलकर रख दी थी। अब गडकरी ने भी सरकार के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। गडकरी ने कहा, ह्यदेश में गरीबी बढ़ रही है, पैसा और संपत्ति चंद अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रही हैह्न नागपुर में सीए छात्रों के लिए एक सेमिनार में बोलते हुए गडकरी ने देश की प्रगति की असली तस्वीर सामने रखी। अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण हो रहा है और यह सही नहीं है, संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, गडकरी ने भी अपनी राय रखी। सिर्फ इसलिए नहीं कि गडकरी ने ऐसा कहा, बल्कि देश में हो रही घटनाएं और हकीकत भी यही कहती हैं। देश की १४० करोड़ की आबादी में से १०० करोड़ से अधिक लोगों के पास सिर्फ अपनी कम से कम जरूरतों पर खर्च के लिए ही पैसे हैं। उनके पास दूसरे खर्चों के लिए पैसे नहीं बचते। सिर्फ १३-१४ करोड़ लोगों के पास ही **न्यूनतम जरूरतों को पूरा करके**

अतिरिक्त खर्च करने की वित्तीय क्षमता है। देश के सबसे गरीब ५० फीसदी लोगों की आय २२.२ प्रतिशत से घटकर १५ प्रतिशत पर आ गई है। देश में मध्यम वर्ग की हालत भी अलग नहीं है। उनकी आय आधी हो गई है और बचत ५० साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, वहीं अमीरों की संख्या भले ही बढ़ी नहीं है, लेकिन अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस तरह के कागजी घोड़े दौड़ाने में मशगूल है कि गरीबी कम हो रही है और पिछले बारह वर्षों में देश में गरीबों का प्रतिशत २७.१ प्रतिशत से घटकर ५.३ प्रतिशत हो गया है। यदि आपके अनुसार, देश का केवल ५ प्रतिशत हिस्सा ही गरीब है तो आपकी सरकार को ८५ प्रतिशत लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने की क्या जरूरत है? मराठवाड़ा के वृद्ध किसान अंबादास पवार को बैल खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण खुद को हल पर क्यों जोतना पड़ा? देश के आम किसानों को आज मौसम की मार और सरकार दोनों के हमलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? किसानों की आत्महत्या थमने को तैयार नहीं है। रविवार को बीड के एक युवा किसान राम फताले ने साहूकारों द्वारा परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में पिछले सिर्फ तीन महीनों में ही ७६७ किसानों ने आत्महत्या

कर ली है। पूरे देश में पिछले १२ सालों में यही संख्या आठ हजार से ज्यादा है।

रूसी हमलों में यूक्रेन में कम से कम 11 नागरिकों की मौत, 80 से अधिक घायल

कीव/मॉस्को। यूक्रेन में जारी रूसी हमलों में एक बार फिर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, बीते 24 घंटों में रूस के हवाई हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला रातभर दागे गए 100 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जानकारी दी कि बीते एक सप्ताह में रूस ने यूक्रेन पर 1,270 ड्रोन, 39 मिसाइलें, और लगभग 1,000 शक्तिशाली ग्लाइड बम दागे हैं। उन्होंने कहा कि, वायु रक्षा जीवन की रक्षा के लिए सबसे अहम है, और यह भी बताया कि यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर ड्रोन निर्माण बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। रूसी हमले में हताहतों के क्रम में यूक्रेन के ओडेसा में एक व्यक्ति की मौत हुई। जबकि खारकीव में एक की मौत हुई और 71 लोग घायल हुए। वहीं, कीव के दो जिलों में ड्रोन मलबे से क्षति। सुमी क्षेत्र में 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। डोनेट्स्क में 7 की मौत और 9 लोग घायल हुए। साथ ही, रूस ने पांच दिनों में तीसरी बार यूक्रेनी सैन्य भर्ती केंद्रों को निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन की नई सेना भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया है।

आयरलैंड के पास्कल डोनोहो तीसरी बार यूरोग्रुप के अध्यक्ष निर्वाचित

ब्रसेल्स। आयरलैंड के वित्त मंत्री पास्कल डोनोहो को यूरोजोन के 20 सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए गठित यूरोग्रुप का अध्यक्ष तीसरी बार चुना गया है। सर्वसम्मति से हुए इस चुनाव के बाद डोनोहो का नया कार्यकाल 13 जुलाई 2025 से शुरू होगा, जो ढाई वर्षों तक चलेगा। डोनोहो 13 जुलाई 2020 से यूरोग्रुप के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पिछले दो कार्यकालों के दौरान यूरोपीय संघ की बजट नीति, डिजिटल यूरो, पूंजी बाजार संघ और बैंकिंग यूनियन जैसे प्रमुख मुद्दों पर नेतृत्व किया है। अपने पुनर्निर्वाचन पर डोनोहो ने कहा, 2020 से यूरोग्रुप के अध्यक्ष के रूप में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मुझे खुशी है कि मेरे साथी मंत्रियों ने तीसरे कार्यकाल के लिए मुझ पर विश्वास जताया। मैंने हमेशा एक निष्पक्ष और ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, और आगे भी सभी देशों की आवाज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करता रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद यूरोजोन की स्थिरता और लचीलापन उल्लेखनीय रहा है, और अब उनकी प्राथमिकता इसे और अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाना है। डोनोहो के अगले कार्यकाल में बजटीय समन्वय, डिजिटल यूरो की दिशा में प्रगति, बैंकिंग यूनियन और पूंजी बाजार को एकीकृत करने जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है.।

रूसी परिवहन मंत्री ने पद से हटाए जाने के कुछ घंटों बाद की आत्महत्या

मॉस्को। देश के परिवहन मंत्री रोमन स्तारवोयत का शव पद से हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद मॉस्को के एक उपनगर में मिला है। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रोमन स्तारवोयत की बर्खास्तगी ऐसे समय की, जब रूसी हवाई अड्डों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के चलते यात्राओं में भारी अव्यवस्था फैली हुई है। बीते सप्ताहांत रूस के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर 240 से अधिक उड़ानें देर से रवाना हुईं और करीब 160 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार इन व्यवधानों को लेकर सरकार के भीतर असंतोष था और मंत्री पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया गया था। रोमन स्तारवोयत को हटाने के तुरंत बाद राष्ट्रपति पुतिन ने उनके स्थान पर उप मंत्री और नोवगोरोद क्षेत्र के पूर्व गवर्नर आंद्रेई निकितिन को कार्यवाहक परिवहन मंत्री नियुक्त किया।

पीएम नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बताया 'ट्यूमर', बोले- हमने उसे हटा दिया

वाशिंगटन । ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा के कुछ दिन बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों के 'ट्यूमर' को हटा दिया है, लेकिन निगरानी जरूरी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच (इजरायल और अमेरिका के बीच साझेदारी) की साझेदारी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने कहा, अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ निर्णायक परिणाम हासिल किया। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर से पहले पत्रकारों से कहा, हमने इजरायल की जान को खतरे में डाल रहे दो ट्यूमर (परमाणु ट्यूमर और बैलिस्टिक मिसाइल ट्यूमर) को कुछ हद तक रोक दिया है। नेतन्याहू ने कहा, वे लोग ऐसी 20,000 चीजें (मिसाइलें) बनाने और उन्हें न्यू जर्सी जैसे छोटे देश पर छोड़ने की योजना बना रहे थे। कोई भी देश इतना हमला झेल नहीं सकता। जब आपके सामने दो ऐसी चीजें हों जो आपको मार सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें हटाना होगा और हमने अपने संयुक्त प्रयास से ऐसा किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा, जब आप एक ट्यूमर को हटाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो दोबारा नहीं आ सकता। आपको हालात पर लगातार नजर रखनी होती है, ताकि कोई उसे वापस लाने की कोशिश न कर सके।

नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया, दोनों ने ईरान पर हमले का जश्न मनाया

एजेंसी

वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सोमवार रात यहां व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डिनर में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने ईरान पर हमले का जश्न मनाया। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया किया है। अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी न्यूज और सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू ने डिनर से पहले पत्रकारों को संबोधित किया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। इस दौरान नेतन्याहू ने राष्ट्रपति के शांति और सुरक्षा के प्रयासों की सराहना की। साथ ही डिनर के दौरान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार समिति को सौंपा गया पत्र भेंट किया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप एक के बाद एक क्षेत्र में शांति

स्थापित कर रहे हैं। इसलिए उनका नाम नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप शांति पुरस्कार के हकदार हैं। शांति का नोबल ट्रंप को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच 60 दिन के युद्ध विराम के प्रस्तावित समझौते पर अभी काम चल रहा है। ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह यूक्रेन को और हथियार भेजने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान कहा कि यूक्रेन की रक्षा बहुत जरूरी है। उसे हथियार भेजने होंगे। इससे पहले दिन में प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। इस साल व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ईरान के खिलाफ हमलों के बारे में कहा, यह एक ऐतिहासिक जीत है। इसने मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह गाजा संघर्ष को जल्द ही समाप्त होते देखना चाहते हैं। वाशिंगटन में इजराइल के पूर्व राजदूत माइकल ओरेन ने कहा कि आने वाला समय बहुत सकारात्मक होगा। रविवार को वाशिंगटन के लिए रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने तेल अवीव में कहा, यह मौका साझा दुश्मन (ईरान) पर बड़ी जीत का जश्न मनाने का है। उन्होंने कहा कि अब गाजा में लड़ाई में 60 दिनों का विराम लगेगा।

नेपाल में दाऊद का 'वजीर' यूनुस खौफ में, जमानत मिली, कहा-नहीं जाना जेल से बाहर

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में अंडर वर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का वजीर यूनुस अंसारी खौफ में है। उसे आशंका है कि जेल से बाहर आने पर उस पर हमला हो सकता है। काठमांडू जिला अदालत ने गैर कानूनी रूप से संपत्ति अर्जित करने के मामले में अंसारी को 15 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मगर उसने जेल से बाहर आने पर इनकार कर दिया है। नेपाल में जाली भारतीय करेंसी नेटवर्क केस में 7 साल जेल की सजा काट कर हाल ही में रिहा होने वाले अंसारी को पाकिस्तान से गैरकानूनी तरीके से 10 करोड़ रुपये नेपाल में लाने और एक टीवी चैनल में इन्वेस्ट करने के आरोप में उसे दोबारा हिरासत में लिया गया था। जिला अदालत ने उसे जमानत प्रदान की। केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो की जिला अदालत में दाखिल चार्जशीट में अंसारी पर पाकिस्तान की खुफिया

एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने, आईएसआई के इशारे में जाली भारतीय नोट का कारोबार करने और पाकिस्तान से 10 करोड़ रुपये अवैध तरीके से नेपाल लाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो का कहना है कि अंसारी ने काली कमाई नेपाल के नेशनल टीवी न्यूज चैनल में इन्वेस्ट की है।

प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ब्रासीलिया, हवाई अड्डे और होटल पर जोरदार स्वागत

एजेंसी

ब्रासीलिया (ब्राजील)। भारतीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (स्थानीय समय) ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी का रक्षामंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्हो ने ब्रासीलिया हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में सांस्कृतिक आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के आखिरी चरण में 09 जुलाई को नामीबिया जाएंगे। वो नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों के यात्रा पर हैं। वो सबसे पहले घाना गए। इसके बाद उन्होंने कैरेबियन देश-त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना गए। अब विदेश दौरे के चौथे पड़ाव पर चार दिनों के लिए वो ब्राजील में हैं। यहां के रियो डी जेनेरियो में उन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहां से अब वे ब्रासीलिया पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वागत समारोह में ब्राजील के पारंपरिक

सांबा रेगे का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की यात्रा पर राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे। उन्होंने वहां प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया। भारतीय समुदाय के सदस्य भारतीय झंडे लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए होटल के बाहर एकत्र हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत करने आए बच्चों से भी बातचीत की। होटल में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी देखा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा, भारत-ब्राजील की दृढ़ साझेदारी में नए कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे हैं।

पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में दुहाई, तीन आतंकी समूह उसके खिलाफ कर रहे अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल

एजेंसी

वाशिंगटन। पराई धरती से आतंकी हमलों की पीड़ा अब पाकिस्तान को समझ में आई है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नाम लेकर अपना दुखड़ा रोया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने महासभा में कहा कि तीन आतंकी समूह अफगानिस्तान के अंदर अनियंत्रित स्थानों से काम कर रहे हैं। डॉन अखबार के अनुसार, अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के पास प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और मजीद ब्रिगेड जैसे आतंकवादी समूहों के बीच बढ़ते सहयोग के विश्वसनीय सबूत हैं। इनका उद्देश्य देश के रणनीतिक बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को निशाना बनाना है। राजदूत अहमद ने कहा कि इनमें से कई हमले अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से किए गए हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सेनाएं 2021 में अफगानिस्तान से अपनी वापसी

के बाद छोड़ गई थीं। उन्होंने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान स्थित आतंकवादियों ने पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से परिष्कृत हमले करने के लिए किया है। पाकिस्तान के दूत ने कहा कि टीटीपी में लगभग 6,000 लड़ाके हैं। अफगानिस्तान की धरती से संचालित होने वाला यह सबसे बड़ा आतंकवादी समूह है। यह समूह न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सक्रिय अन्य समूहों में आईएस-खोरासन, अल कायदा और विभिन्न बलूच अलगाववादी गुट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान उन आतंकवादियों के लिए प्रजनन स्थल न बने जो उसके पड़ोसियों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा हैं।

बांग्लादेश पत्रकारों के लिए यातनागृह, 11 माह में 412 पर मुकदमा, 39 गिरफ्तार, 168 की मान्यता रद्द

एजेंसी

ढाका। ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी (डीआरयू) ने बांग्लादेश में पत्रकारों की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। डीआरयू के पूर्व अध्यक्ष सैयद शुकुर अली शुवो समेत 51 पत्रकारों ने खुलासा किया है कि 11 महीने की अवधि में 412 पत्रकारों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से 39 को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। यही नहीं 168 की प्रेस मान्यता रद्द कर दी गई और 100 से अधिक लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, पत्रकारों ने जारी बयान में सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना करते हुए जेल में बंद पत्रकारों की रिहाई की मांग करते हुए मीडियाकर्मियों के खिलाफ जारी उत्पीड़न और धमकियों की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि हाल के दिनों में मुल्क में पत्रकारों पर हत्या के आरोप, नौकरी से निकाले जाने,

मीडिया आउटलेट्स पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। निरंकुश भीड़ भी पत्रकारों की जान लेने में पीछे नहीं रही। बयान में अफसोस जताया गया है कि इन घटनाओं के लिए किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। बयान में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में प्रकाशित रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक 10 पत्रकारों की हत्या हुई। 300 से अधिक पत्रकारों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं कई पत्रकारों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और 101 मीडिया कर्मचारियों को राष्ट्रीय और स्थानीय प्रेस क्लबों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बयान के अनुसार, पत्रकार संघों पर कब्जा कर लिया गया है। ढाका यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का कार्यालय पिछले 11 महीने से बंद है। जमानत प्राप्त करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कई पत्रकार बिना किसी सुनवाई के महीनों तक जेल में बंद रहे। यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। बयान में सरकार से मांग की गई है हमें उम्मीद है कि अंतरिम सरकार राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर स्थिति में सुधार करेगी। भीड़ की हिंसा पर अंकुश लगाएगी और सभी प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त करके पत्रकारों की पेशेवर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बयान में इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है।

नेपाल और चीन को जोड़ने वाला वाला पुल बाढ़ में बहा

एजेंसी

काठमांडू। चीन में बीती रात को आई बाढ़ के कारण नेपाल के सीमा क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। नेपाल और चीन के बीच रहे एकमात्र व्यापारिक नाका रसुवागढ़ी और चीन को जोड़ने वाला पुल बाढ़ में बह गया है। चीन से नेपाल के लिए निर्यात किए गए सैकड़ों इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां पानी में बह गई हैं। सामान से लदा कंटेनर नदी में बहता हुआ दिख रहा है। सीमा पर खड़े कई ट्रक भी पानी में डूब गए हैं जिसके कारण उसमें

रखा सामान के खराब होने की संभावना अधिक है। इस बाढ़ के कारण नेपाल के तरफ करीब 16 लोगों के लापता होने की खबर है। रसुवागढ़ी के जिला प्रशासन की तरफ से काठमांडू के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को दी गई जानकारी के मुताबिक बीती रात को ड्यूटी पर रहे नेपाल पुलिस के 3 जवान, 3 कंटेनर ड्राइवर, 6 नेपाली कामदार और 4 चीनी कामदार लापता बताए जा रहे हैं। आज सुबह से ही नेपाली सेना राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ लोगों को बचाया भी है। बाढ़ में फंसे 9 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। रसुवागढ़ी जिला प्रशासन के मुताबिक मानवीय क्षति और अधिक हो सकती है।

टेक्सास में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा की मौत, विपक्ष के संसाधनों की कमी के आरोप को ट्रंप प्रशासन ने खारिज किया

एजेंसी

वाशिंगटन। टेक्सास में बाढ़ से जानमाल की बड़ी क्षति हुई है। इस विभीषिका को अमेरिका के 100 साल के इतिहास में सबसे भयावह बताया जा रहा है। टेक्सास में बाढ़ से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से लड़कियों का कैंप का तहस-नहस हो गया। मृतकों में 27 लड़किया भी शामिल हैं। विपक्ष ने राहत और बचाव कार्य में संसधानों की कमी के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। प्रशासन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को बेडमिनस्टर गोल्फ कोर्स से बाहर निकलते समय संवाददाताओं से कहा, यह सौ साल की सबसे भयावह आपदा है। इसे देखना बहुत त्रासद है। उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय मौसम सेवा सहित संघीय एजेंसियों में की गई

छंटनी के कारण यह आपदा और बढ़ गई है, तो उन्होंने अपना जवाब टाल दिया। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट और अल्पसंख्यक नेता सीनेटर चक शूमर ने वाणिज्य विभाग के कार्यवाहक महानिरीक्षक को लिखे पत्र में इस बात की जांच करने की मांग की है कि क्या प्रमुख स्थानीय राष्ट्रीय मौसम सेवा स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी ने बाढ़ को विकराल बना दिया। कनेक्टीकट के डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस्टोफर एस. मर्फी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मौसम विज्ञानियों पर ट्रंप के मूर्खतापूर्ण कार्रवाई का यह परिणाम है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार दोपहर प्रेस ब्रीफिंग में इस तरह के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मौसम सेवा के पास पर्याप्त कर्मचारी हैं। लेविट ने कहा कि कई डेमोक्रेट इसे राजनीतिक खेल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शोक के वक्त इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी ठहराना वाजिब नहीं है। ट्रंप प्रशासन के रिपब्लिकन सहयोगी भी बचाव में आगे आए हैं। टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए विरोधियों को दोषी ठहराना अच्छी बात नहीं। बाढ़ से तबाह हुए टेक्सास के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चिप रॉय ने कहा कि शोक के वक्त उंगली उठाना अपमानजनक होता है।

ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर 25 फीसद टैरिफ लगाया

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर 25 फीसद टैरिफ की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान को पहली अगस्त से अपने निर्यात पर 25 प्रतिशत का नया टैरिफ वहन करना पड़ेगा। उन्होंने दर्जनों अन्य देशों के खिलाफ अधिक टैरिफ पर प्रतिबंध को भी पहली अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। यह कल से प्रभावी होने वाला था।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, इसके बाद बाजार में गिरावट आई। निवेशकों ने दरों को अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए उचित नहीं माना। ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर टैरिफ की घोषणा

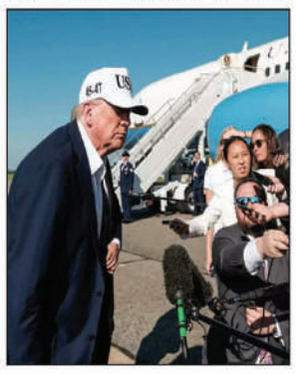

के बाद सोशल मीडिया पर कई पत्र भी पोस्ट किए। इनमें अन्य देशों पर उच्च टैरिफ का विवरण दिया गया- म्यांमार और लाओस के लिए 40 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका के लिए 30 प्रतिशत और कजाकिस्तान और मलेशिया के लिए 25 प्रतिशत। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन माह से ट्रंप प्रशासन एक दर्जन से अधिक देशों के साथ व्यापार समझौते करने की कोशिश कर रहा है। अब तक, अमेरिका ने केवल ब्रिटेन और वियतनाम के साथ ही प्रारंभिक समझौते किए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत अन्य देशों की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। जापान और दक्षिण कोरिया ट्रंप प्रशासन के साथ समझौता करने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें चिंता है कि भविष्य में उन पर और अधिक टैरिफ थोपा जा सकता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो एशिया की पहली यात्रा पर, मलेशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल

एथेंस। वॉशिंगटन/कुआलालंपुर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार तक अपनी पहली एशियाई यात्रा पर होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस दौरान वह मलेशिया में आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे और आसियान (एएसईएएन) देशों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, एशिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रुबियो का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराना है, जो कि स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हो। मलेशिया प्रवास के दौरान रुबियो मलेशियाई शीर्ष अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे, जिसमें रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर बातचीत होने की संभावना है। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच अमेरिका अपनी सक्रिय भूमिका को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

पाकिस्तान में मानसूनी बारिश में 19 की मौत, बाढ़ का खतरा बढ़ा

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मानसून की पहली बारिश में 19 लोगों की मौत हो गई। यह जनहानि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुई है। इस बीच राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र ने आज और कल मुल्क के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का पूर्वानुमान जारी किया है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र ने 10 जुलाई तक मध्यम से भारी मानसूनी बारिश और लगभग सभी नदियों में बाढ़ का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और अन्य अधिकारियों को संभावित आपातकालीन स्थितियों, खासकर बाढ़ से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने बताया कि बलूचिस्तान में पिछले 48 घंटों में हुई मानसून की बारिश के कारण कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान के लगभग 22 जिले बारिश से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 22 घर क्षतिग्रस्त और पांच नष्ट हो गए। पीडीएमए के अधिकारियों ने कहा कि इससे ईरान की सीमा से सटा वाशुक जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां खड़ी फसलें बह गई और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। पुलिस और आपातकालीन

सेवाओं ने बताया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के विभिन्न हिस्सों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में तीन बच्चों सहित कम से कम छह लोग डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में मलकंद, बुनेर, मनशेरा और करक जिलों में छह लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री शहबाज ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बचाव एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि तरबेला बांध स्पिल-वे के संचालन से सिंधु नदी के किनारे निचले जिलों में बाढ़ से स्थिति बिगड़ सकती है। अधिकारियों के अनुसार, काबुल, सिंधु, झेलम और चिनाब सहित सभी प्रमुख नदियों में पानी का प्रवाह तेजगति से बढ़ने की उम्मीद है। स्वात और पंजकोरा नदी के अलावा अन्य सहायक नदियां कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती हैं।

बांग्लादेश की बढ़ी आर्थिक चुनौतियाँ: ट्रंप का 35फीसदर टैरिफ निर्यात पर लागू

एजेंसी
मुंबई। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी उत्पादों के निर्यात पर 35त्र 'पारस्परिक' टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। यह कदम बांग्लादेश के लिए आर्थिक मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासकर उसके सबसे बड़े निर्यात क्षेत्र, तैयार परिधान उद्योग पर इसका गहरा असर पड़ने की आशंका है। वहीं, इस खबर ने भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए नए अवसर खोल दिए हैं, जिससे भारतीय कपड़ा कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर इस फैसले की जानकारी देते हुए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को संबोधित एक पत्र भी साझा किया। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि यह 35त्र का टैरिफ आवश्यक है ताकि बांग्लादेश की उन व्यापार नीतियों और बाधाओं को ठीक किया जा सके जिनके कारण अमेरिका के साथ एक बड़ा और अस्थिर व्यापार घाटा बना हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि यदि बांग्लादेश अपने टैरिफ में वृद्धि करता है, तो अमेरिकी टैरिफ दर में उतनी ही वृद्धि कर दी जाएगी। यह नई टैरिफ दर बांग्लादेश के लिए पहले से लागू औसत 15त्र शुल्क से काफी अधिक है, और यह वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों (जिसने अमेरिका के साथ एक नए व्यापार समझौते के तहत 20त्र टैरिफ हासिल किया है) की तुलना में भी काफी ऊंची है।

भारतीय अधिकारियों को जापानी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए जीका से 17 करोड़ रु. का अनुदान

दिल्ली। जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीका) ने 'मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) परियोजना' के तहत भारत को 28.8 करोड़ जापानी येन (17 करोड़ रुपये) का अनुदान देने के लिए चार वर्ष का करार किया है जिसके तहत भारतीय अधिकारियों को जापान के विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीका की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इसके अंतर्गत हर वर्ष भारत के 16 युवा अधिकारी जापान में विश्वविद्यालयों में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में भाग ले सकेंगे। अनुदान समझौते पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की अतिरिक्त सचिव मनीषा सिन्हा और जीका इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि ताकेउची ताकुरो के बीच हस्ताक्षर किए गए। जापान सरकार 2024 से यह छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। यह कार्यक्रम भारतीय सरकारी अधिकारियों को जापानी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के माध्यम से मूल्यवान क्षमता विकास के अवसर प्रदान करेगा। यह समझौता चार वर्ष के लिए है और इसमें भारतीय नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हर वर्ष 9 अधिकारियों का चयन किया जाएगा।

शेयर बाजारों में कारोबार सीमित, नरमी की धारणा के साथ प्रमुख सूचकांक पिछले स्तर पर बने रहे

मुंबई। भारतीय बाजारों में सीमित कारोबार और नरमी की धारणा के बीच बैंकिंग, आटो और आईटी क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली के दबाव के साथ प्रमुख सूचकांक पिछले सत्राहांत के स्तर पर बने रहे। बाजार विश्लेषकों के अनुसार निवेशक अमेरिका में आयात शुल्क पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले की प्रतीक्षा में कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रहे हैं। बाजार को स्पष्ट संकेतों का इंतजार है और आने वाले दिनों में निवेशक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता वार्ता के नतीजे तथा कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजों से संकेत ले सकते हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह 83,398.08 पर खुलने के पूर्वाह्न में एक समय 83,516.82 तक चढ़ गया था। यह तेजी ज्यादा देर नहीं टिकी और कारोबार के दौरान 83,262.23 तक गिरने के बाद अंत में पिछले बंद के मुकाबले 9.61 यानी 0.01 प्रतिशत की तेजी नाममात्र की बढ़त के साथ 83,442.50 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 83,432.89 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर हानि और 18 लाभ में बंद हुए। लाभ में रहे शेयरों में हिंदुस्तान लीवर तीन प्रतिशत बढ़त के साथ बंद हुआ। कोटक बैंक, ट्रेंट, रिलायंस, आईटीसी, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, सनफार्मा, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और अडानी पोर्ट भी हल्के लाभ में रहे।

भारतीय परिवारों पर 'छोटे कर्ज' का बोझ

नई दिल्ली। भारतीय परिवारों पर छोटे-छोटे कर्जों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब लोग न केवल बड़े खर्चों जैसे घर या गाड़ी के लिए, बल्कि अपनी आम जरूरतों और दैनिक उपभोग को पूरा करने के लिए भी लोन ले रहे हैं। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन रही है, जहाँ बढ़ती खपत क्रेडिट पर आधारित होती जा रही है, जबकि बचत दर में कमी आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद से यह चलन तेजी से बढ़ा है। आय में अनिश्चितता और बढ़ती महंगाई के कारण कई परिवारों के लिए अपनी मासिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, और छोटे उपभोग ऋण का सहारा लिया जा रहा है। यह प्रवृत्ति, एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर परिवारों को कर्ज के जाल में धकेलने का जोखिम पैदा कर रही है।

मक्का तीसरी सबसे बड़ी फसल, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तरह के शोध की आवश्यकता : शिवराज सिंह

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित 11वें भारत मक्का समिट-2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिवराज सिंह ने मक्का उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने यहां कहा कि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी नीति है- देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, खेती को लाभ का धंधा बनाना, पोषणयुक्त आहार कैसे हमारी जनता को मिले, उसकी कोशिश करना है। शिवराज सिंह ने कहा कि मक्का में अभी कई चीजों

की जरूरत है। मक्का तीसरी सबसे बड़ी फसल हो गई है, पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। स्टार्च कम है, कई तरह के शोध की ज़रूरत है। अमेरिका, ब्राज़ील में कितना मक्का उत्पादन होता है। हम जेनिटिक्ली मॉडिफाइड (जीएम) बीज का इस्तेमाल नहीं करते, इसके बावजूद उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि मक्का में उत्पादन कैसे बढ़े, क्योंकि 1990 के दशक में केवल 10 मिलियन टन उत्पादन था, अब ये बढ़कर लगभग 42.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है और 2047 तक यह 86 मिलियन टन पहुंच सकता है। चौहान ने कहा कि हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी धन्यवाद देना चाहिए कि मक्का की कई नई किस्में-265 वैरायटी विकसित की हैं, जिनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी हैं, जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न शामिल है और करीब 30 बायोफोर्टिफाइड भी हैं, यानी काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है काम और करने की जरूरत है। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी है। बीच में मक्का के रेट काफ़ी गिर गए थे, लेकिन एमएसपी, एथनॉल लक्ष्य सहित सरकार की नीतियों से दाम फिर बढ़े हैं। मक्का के किसानों को ठीक दाम मिले, इसकी हम कोशिश करते रहेंगे।

डॉलर की तुलना में 46 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुई भारतीय मुद्रा

एजेंसी
नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी और डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण आज डॉलर की तुलना में रुपये में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 46 पैसे की कमजोरी के साथ 85.86 (अस्थायी) के स्तर पर बंद हुआ। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा 85.40 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी।इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आज रुपया डॉलर की तुलना में 17 पैसे की कमजोरी के साथ 85.57 के स्तर पर खुला था। दिन के कारोबार में रुपया कमजोर होकर 86.03 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया। हालांकि डॉलर की आवक बढ़ने पर भारतीय मुद्रा मजबूत होकर 85.51 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक भी आई। पूरे दिन के काराबोर के बाद भारतीय मुद्रा 85.86 रुपये (अस्थायी) प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती और कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी होने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी के कारण भी रुपये की कीमत में आज गिरावट का रुख बना है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खड़े होने वाले देशों पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और इस नीति में कोई छूट भी नहीं दी जाएगी। कैपेक्स गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात में रुपये की कीमत में और गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। ट्रेड डील को लेकर अभी तक अनिश्चितता का माहौल बना रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है।

सर्राफा बाजार में उछला सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

एजेंसी
नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोना आज 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। इसी तरह चांदी के भाव में भी आज 100 रुपये की सांकेतिक तेजी नजर आ रही है। भाव में उछाल आने की वजह से आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 98,840 रुपये से लेकर 98,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 90,600 रुपये से लेकर 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में मामूली तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 98,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 98,890 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,650 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 90,600 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 98,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 90,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 98,990 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना महंगा हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 98,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

नौ जुलाई को 25 करोड़ कर्मचारी करेंगे देशव्यापी हड़ताल

एजेंसी
नई दिल्ली। बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के देशव्यापी हड़ताल पर जाने की संभावना है। ऐसे में बुधवार, 9 जुलाई को देशभर में एक बार फिर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती है। देशव्यापी हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के एक मंच ने किया है। इससे बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन, राजमार्ग, निर्माण और यहां तक कि विभिन्न राज्यों में राज्य परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं बाधित होने की संभावना है। 9 जुलाई को देशभर में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी सरकार की ÷मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों÷ के विरोध में देशव्यापी हड़ताल यानी भारत बंद पर जाने की उम्मीद है। इससे देशभर में जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।एनएमडीसी पिछले वर्ष श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्री मांगों का एक चार्टर सौंपा था। इसमें कहा गया है कि सरकार पिछले 10 वर्षों से वार्षिक श्रम

लिमिटेड और अन्य गैर-कोयला खनिज, इस्पात, राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के यूनियन नेताओं ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का नोटिस दिया है। इससे पहले श्रमिक संघ मंच ने अपने हालिया बयान में कहा कि मंच ने सम्मेलन आयोजित नहीं कर रही है और श्रम बल के हितों के विपरीत निर्णय ले रही है। उल्लेखनीय है कि ट्रेड यूनियनों ने इससे पहले 26 नवंबर, 2020, 28-29 मार्च, 2022 और पिछले साल 16 फरवरी को इसी तरह की देशव्यापी हड़ताल की थी।

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की कृषि और बागवानी योजनाओं के लिए 3800 करोड़ रुपये की दी सैद्धांतिक मंजूरी

एजेंसी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, ग्राम्य विकास एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। उन्होंने प्रदेश की कृषि एवं उससे जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विस्तार के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की कृषि बागवानी आवश्यकताओं व किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए राज्य सरकार प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार ने कृषि व बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगभग 3,800 करोड़ रुपये की व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन एवं पारम्परिक कृषि को बढ़ावा देने जैसे विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने राज्य की कृषि संबधि योजनाओं के लिए 3800 करोड की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनका आभार जताते हुए कहा कि यह सहयोग राज्य के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि बाड़ निर्माण के लिए 1,052.80 करोड़ रुपये की आवश्यकता चिह्नित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में 10,000 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गई है, जिससे लघु, सीमांत किसान एवं महिलाएं लाभान्वित होंगी। पारम्परिक पोषक फसलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत 134.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए राज्य को सीड हब के रूप में विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये की योजना भी तैयार की गई है। सेब उत्पादन को प्रोत्साहन, भंडारण और विपणन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। नकदी फसलों जैसे कीवी के संवर्धन एवं खेती को वन्यजीवों से संरक्षित करने के लिए 94 करोड़ रुपये की आवश्यकता दर्शाई गई है। कृषि व बागवानी क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 885.10 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। ड्रैगन फ्रूट जैसी कम जोखिम वाली फसलों को प्रोत्साहित हेतु 42 करोड़ रुपये की योजना भी तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में राज्य सरकार सक्रियता से कार्य कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 36.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटल सर्वेक्षण के लिए के अंतर्गत 378.50 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं को कृषि क्षेत्र में दक्ष बनाने हेतु 14 करोड़ रुपये तथा एग्रीटूरिज्म स्कूल की स्थापना हेतु 14 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है।

वित्तीय सेवा सचिव ने फिनटेक से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का आग्रह किया

एजेंसी
नई दिल्ली। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों से वित्तीय समावेश को बढ़ाना देने के लिए ऑफलाइन भुगतान समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि फिनटेक कंपनियां अपनी ताकत और नवाचार का लाभ उठाकर न केवल आम जनता तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाएं, बल्कि धोखाधड़ी, हैकिंग और अन्य साइबर खतरों के खिलाफ मजबूत समाधान विकसित करें।एम. नागराजू ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित तीसरे वित्तीय समावेशन और फिनटेक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान यह बात कही। डीएफएस सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि यह हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत भुगतान प्रणाली में कई देशों से बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में अपने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को कई अन्य देशों में विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। नागराजू ने कहा कि हमारी उपस्थिति सात देशों में है और हम कुछ और देशों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। शायद इस साल हम और भी देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जहां नागरिक हमारे यूपीआई सिस्टम के माध्यम से भुगतान करेंगे। उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का अधिक से अधिक उपयोग करें। नागराजू ने फिनटेक कंपनियों से ऑफलाइन पेमेंट के लिए भुगतान समाधान पर ध्यान देने का अनुरोध करते हुए इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वित्तीय समावेशन को वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में एक प्रमुख कारक के रूप में मान्यता मिल रही है।

भारत में पर्यटन की खपत बढ़ने से भविष्य 'बहुत मजबूत और उज्ज्वल' : चंद्रशेखरन

एजेंसी
नई दिल्ली/मुंबई। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने विश्वास जताया कि भविष्य बहुत मजबूत और उज्ज्वल है, क्योंकि भारत में बढ़ती खपत से यात्रा क्षेत्र की वृद्धि को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि टाटा समूह अपनी सभी कंपनियों में सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, यह उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। देश की सबसे बड़ी आतिथ्य सेवा कंपनी आईएचसीएल के शेयरधारकों को संबोधित करते हुए एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर होटलों की कुल संख्या 700 तक पहुंचाना, जबकि राजस्व को दोगुना कर 15 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि समूह को पता है कि विस्तार योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए उसे इस मुद्दे पर और अधिक काम करने की जरूरत है।

टाटा संस के चेयरमैन ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपने संबोधन की शुरुआत हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देकर की। इसके साथ ही पिछले साल अक्टूबर में रतन टाटा के निधन पर गहरी क्षति भी व्यक्त की। उन्होंने आईएचसीएल की वार्षिक आम बैठक में अपने विचार साझा किए। वे एयर इंडिया दुर्घटना के बाद किए गए सुरक्षा उपायों और टाटा समूह की अन्य कंपनियों में ऐसी त्रासदियों से बचने के बारे में शेयरधारकों के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा समूह की कंपनियों में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रमुख कंपनियों के सीईओ का एक समूह बनाया गया है। उन्?होंने कहा, हमारे जानने वाले एक भी व्यक्ति को खोना एक त्रासदी है, लेकिन एक साथ इतनी सारी मौतें होना समझ से परे है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन पर भी गहरी क्षति की भावना व्यक्त करना चाहूंगा। चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत में सेवा क्षेत्र करीब 8 फीसदी की दर से बढ़ रहा है, विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा भी साल-दर-साल बढ़ रही है, तथा यह धीरे-धीरे 10 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा, भविष्य बहुत मजबूत और उज्ज्वल दिख रहा है।

कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी: सोनोवाल

एजेंसी
गुवाहाटी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार के बीच संपर्क बढ़ाने की रणनीतिक पहल कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारत सरकार के कई पहलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लगभग 50 हजार युवाओं को समुद्री नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।सोनोवाल ने बताया कि बहुआयामी रणनीति का उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना, समुद्री रसद को बढ़ाना और क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कार्गो हैंडलिंग, क्षमता और तटीय शिपिंग में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को बदल दिया है।उन्होंने कहा कि प्रमुख बंदरगाहों ने अपनी क्षमता लगभग दोगुनी कर ली है। महत्वाकांक्षी नए टर्मिनलों के साथ क्रूज पर्यटन बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के 50,000 युवाओं को समुद्री

नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रमुख विधायी और डिजिटल सुधार, हरित शिपिंग पहल और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को मजबूत कर रही हैं। भारत के बंदरगाह अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं, जिनमें से नौ विश्व बैंक के शीर्ष 100 में स्थान पर हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह शीर्ष 20 में पहुंच गया है।

संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के बावजूद मई में भारत-पाक व्यापार जारी रहा

एजेंसी
नई दिल्ली। पाकिस्तान और भारत के बीच संक्षिप्त सैन्य संघर्ष और सीमाओं के लगातार बंद होने के बावजूद दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार मई में, मुख्य रूप से तीसरे देश के माध्यम से जारी रहा। समाचार पत्र 'डॉन' ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि भारत से आयात पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के जुलाई-मई के दौरान तीन साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में भारत से आयात कुल 21.15 करोड़ डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 20.7 करोड़ डॉलर और वित्त वर्ष 2022-23 में 19 करोड़ डॉलर से अधिक था। अकेले मई में - जब पहले सप्ताह में चार दिवसीय संघर्ष छिड़ा था - आयात 1.5 करोड़ डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने के 1.7 करोड़ डॉलर से थोड़ा कम था। हालांकि, भारत को पाकिस्तान का निर्यात नगण्य रहा। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यात क्रमशः 34.4 लाख डॉलर और 3.3 लाख डॉलर रहा - जो द्विपक्षीय व्यापार की अत्यधिक एकतरफा प्रकृति को उजागर करता है। पाकिस्तान और भारत के बीच औपचारिक व्यापार संबंध 2019 से प्रभावित हैं। हालांकि, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, भारत ने कई कदम उठाए।

लुधियाना में मप्र को मिले 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20 हजार रोजगार का होगा सृजन

एजेंसी
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लुधियाना में हुए इंटरैक्टिव सेशन, वन-टू-वन चर्चा और संवाद सत्रों में यहां के उद्योगपतियों से 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 20 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा। इनमें ट्राइडेंट ग्रुप ने 5000 करोड़, रालशन टायर्स लिमिटेड ने 2200 करोड़, वर्धमान इंडस्ट्रीज ने 1581 करोड़, एबी कोटस्पिन इंडस्ट्री ने 1300 और नाहर ग्रुप ने 1100 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। हमने लुधियाना और पंजाब के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित किया। साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य की औद्योगिक नीतियों से भी अवगत कराया है।मुख्यमंत्री पंजाब की उद्योग नगरी लुधियाना में मप्र में निहित निवेश की संभावनाओं के संबंध में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है। देश में औद्योगीकरण बढ़ा है, अब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लुधियाना भारत का मैन्चेस्टर है। यहां के उद्योगपतियों ने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। लुधियाना में निर्मित ए-वन और हीरो साइकिल्स देश-दुनिया में मशहूर हैं। पंजाब के निवेशक देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख ध्वजवाहक हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है, जहां पन्ना जिले में हीरा तो शहडोल में आयरन डिपाजिस्ट्स है। बीते दिनों सिंगरौली जिले में सोने की खदानें भी मिली हैं। मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को मध्यप्रदेश की रत्नगर्भा भूमि में निवेश करने के लिए आत्मीयता से आमंत्रित करते हुए कहा कि यहां व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक मध्य प्रदेश में जितना चाहें, उतने उद्योग-धंधे लगाएं, सरकार पलक-पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी, आपकी हर संभव मदद करेगी। मध्य प्रदेश में उद्योग-धंधे लगाने के लिए जरूरत के मुताबिक भूमि, बिजली, पानी, कुशल कार्यशक्ति सब उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब दोनों भाइयों की तरह हैं। अनाज के उत्पादन में पंजाब बड़ा और मध्यप्रदेश छोटा भाई है। ?अब दोनों भाई मिलकर देश और मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर है। पंजाब वीरों की धरती है, इसकी अलग ही पहचान है। यह गुरु परंपरा की अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश के इंदौर की पहचान स्वच्छता में है, तो लुधियाना की पहचान उद्योगों से है। हम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। आप खुले दिल से और बिना किसी हिचक के निवेश करें, सरकार जितनी हो सकेगी, आपकी उतनी मदद करेगी। कहा कि भारत बदलते दौर में सिरमौर बन रहा है। उद्योगों से कई परिवारों का उदर-पोषण होता है और गरीबों के जीवन में आमदनी का उजाला आता है। यह एक पवित्र कार्य है। उद्योगपति अपने परिवार का पोषण करते हुए दूसरों का भी घर रौशन करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अमर शहीद भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आप लोग यहां भी काम करते रहें और अपने कारोबार का विस्तार करते हुए एक-दो फैक्ट्री मध्य प्रदेश में भी लगाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी उद्योग अनुकूल नीतियों को दुनिया के सामने रखा। हमने उद्योगपतियों को कई सौगातें दी हैं। टेक्सटाईल्स सेक्टर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सैलरी में मध्य प्रदेश सरकार 5000 रुपये की अतिरिक्त मदद देगी। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को साइकिलें बांटी जा रही हैं। साइकिलें मुख्यत÷ पंजाब में ही बनती हैं। यही साइकल मध्य प्रदेश में भी बन सकती हैं। उद्योगपति मध्य प्रदेश में साइकल बनाने की फैक्ट्री लगाएं। भारत दुनिया में सोने की चिड़िया की पहचान रखता था।

नोरा फतेही

के करीबी का निधन, एयरपोर्ट पर रोती दिखीं, फैन करीब आया तो गार्ड ने दिया धक्का

मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर ही रोते हुए देखा गया. अपनी कार से उतरते ही नोरा काफी इमोशनल हो गईं. बताया जा रहा है कि नोरा के किसी बेहद करीबी शख्स का निधन हो गया है. नोरा अपने परिवार का साथ देने के लिए दुख की घड़ी में उनके पास पहुंची हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नोरा की आंटी का निधन हो गया है. इससे एक्ट्रेस को बड़ा झटका लगा है. एक्ट्रेस ये खबर मिलते ही तुरंत मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हो गई थीं. हालांकि एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस को पैपराजी ने अपने कैमरों में कैद कर लिया था. इस दौरान वो बेहद भावुक दिखीं और अपने आंसू मीडिया के कैमरों से छिपाती रहीं.

काले लिबास में रोते हुए दिखीं नोरा

सामने आए एक वीडियो में आप नोरा को पूरे ब्लैक कलर के आउटफिट में देख सकते हैं. वहीं एक्ट्रेस ने काले रंग का चश्मा लगा रखा था, हालांकि इसके बावजूद एक्ट्रेस अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाईं. एयरपोर्ट पर वो ना चाहते हुए भी रोने लगीं. दुख की इस

घड़ी में लोग सोशल मीडया पर एक्ट्रेस के लिए कमेंट्स करते हुए उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं.

बॉडीगार्ड ने दिया फैन को धक्का

इस वीडियो के अलावा एक्ट्रेस का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें नोरा को एयरपोर्ट पर देखकर एक फैन एक्ट्रेस की तरफ सेल्फी के लिए आ जाता है. एक्ट्रेस एक पल के लिए भी उधर कोई ध्यान नहीं देती है. जबकि पीछे से बॉडीगार्ड फैन को पकड़ कर उसे धक्का दे देता है और गुस्से में उसे कुछ कहते हुए भी नजर आता है.

चर्चा में नोरा की इंस्टाग्राम स्टोरी

नोरा फतेही की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है कि उनके किस करीबी का निधन हुआ है. हालांकि एक्ट्रेस के इन वीडियो के साथ उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी लोगों का ध्याना खींच रही है. एक्ट्रेस ने संडे को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इस्लामी आयत का एक हिस्सा शेयर किया, जिसमें लिखा था, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिउन.इसे किसी के निधन (इस्लाम में) के बाद पढ़ा जाता है.

मौत से 2 दिन पहले दुल्हन की तरह सजी थीं श्रीदेवी, इन लोगों के साथ आई थीं नजर

श्रीदेवीज्ये नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेश याद किया जाता रहेगा. महज 4 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया से उनका परिचय हो गया था. बाद में बड़ी होने पर फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रोल निभाए. साउथ फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत की. फिर बाद में बॉलीवुड का रुख किया. श्रीदेवी न सिर्फ बॉलीवुड में कामयाब हुईं बल्कि उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली 'फीमेल सुपरस्टार' भी कहा जाता है.श्रीदेवी ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया था. बॉलीवुड में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था, जिसका सपना हर एक एक्ट्रेस देखती है. अपनी मौजूदगी से श्रीदेवी फिल्मों में चार चांद लगा देती थीं. लेकिन, लाखों-करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ये दिग्गज एक्ट्रेस 54 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई थीं. आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर मौत से दो दिन पहले श्रीदेवी क्यों दुल्हन की तरह सजी थीं और वो किन लोगों के साथ नजर आई थीं ?

2018 में हो गया था निधन

श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था. 24 फरवरी 2018 को उनका निधन हो गया था. वो अपने रिश्तेदार और बॉलीवुड एक्टर मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए अपनी फैमिली के साथ दुबई गई थीं. उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दुबई के एक होटल में एक्ट्रेस मृत पाई गई थीं.

मौत से 2 दिन पहले दुल्हन की तरह सजी थीं श्रीदेवी!

श्रीदेवी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थीं. मोहित की शादी से जुड़ी कई तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर की थी. श्रीदेवी ने निधन से ठीक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट किया था. ये मोहित की शादी से जुड़ी तस्वीर ही थी. इसमें एक्ट्रेस दुल्हन की तरह सजी हुई दिखी थीं. फोटो में उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर और पति बोनी कपूर के अलावा और भी कुछ करीबी लोग दिखाई दे रहे हैं.

300 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्में भी की थीं. बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 1979 की फिल्म 'सोलहवां सावन' से करने वाली श्रीदेवी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में 'हिम्मतवाला', 'चांदनी', 'मिस्टर इंडिया', 'चालबाज', 'जुदाई', 'नगीना', 'फरिश्ते', 'लम्हे', 'खुदा गवाह', 'लाडला' और 'इंग्लिश विंग्लिश' शामिल हैं.

अमाल मलिक के बयान पर डब्बू मलिक का रिएक्शन, कार्तिक आर्यन को लेकर किए खुलासे पर दिया साथ

अमाल मलिक ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए थे. सिंगर अमाल मलिक ने मिर्ची प्लस को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता कार्तिक आर्यन को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें भी दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोग उनके खिलाफ हैं और पावर प्ले कर रहे हैं. अमाल मलिक के इस स्टेटमेंट के बाद उनके पिता और जाने-माने संगीतकार डब्बू मलिक ने अपनी बात सामने रखी है.

हिंदी डिजिटल से बात करते हुए, डब्बू मलिक ने कहा कि अमाल की अपनी सोच है और वे चीजों को खुद ही समझते हैं. अब कोई ये तय नहीं कर सकता कि अमाल की बातें कितनी सही हैं या कितनी गलत. उनकी अपनी राय है और उनके अपने ऑब्जर्वेशन हैं, जो वो खुद ही डेवलप करते हैं. अब वो कितना रेलीवेंट है, कितना नहीं है, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता.

बेटे के सपोर्ट में आगे आए डब्बू मलिक

डब्बू मलिक ने आगे बताया कि उन्हें नहीं लगता कि अमाल की इन बातों से उनके करियर पर कोई बड़ा असर पड़ेगा. हालांकि, उन्होंने माना कि फिल्म इंडस्ट्री इस पर अलग तरीके से सोच सकती है. उन्होंने कहा कि अमाल एक बहुत खुले विचारों वाले इंसान हैं. चाहे उनके गाने हों, उनकी सोच हो, या लोगों से उनका मिलना-जुलना हो, वे अपनी बात बिना झिझक के कहते हैं.

अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं डब्बू मलिक

एक पिता होने के नाते, डब्बू मलिक ने कहा कि वे अपने बेटे की हर तरह से रक्षा (प्रोटेक्ट) करना चाहते हैं, जैसा हर पिता चाहता है. लेकिन उन्होंने चिंता जताई कि कभी-कभी अचानक बातें सामने आती हैं और वायरल हो जाती हैं, जिस पर लोग तरह-तरह की बातें करते हैं. डब्बू मलिक ने बताया कि कार्तिक और सुशांत को लेकर अमाल की बातें उनके लिए भी हैरान करने वाली थीं और वे खुद भी थोड़े परेशान हो गए थे. उन्होंने कहा कि वे आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत भावुक हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों. अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अकेलेपन और दर्द का सामना किया है. कभी-कभी वे खुद को युवाओं से जोड़ पाते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी मुश्किलों को समझकर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले.

बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग

श्रद्धा कपूर

का वीडियो देख भड़की उठीं रवीना टंडन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धा कपूर फ्लाइट में बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ ट्रैवल करती नजर आ रही हैं. वीडियो की चर्चा तब और तेज हो गई जब उस पर रवीना टंडन का रिएक्शन सामने आया. उन्होंने एयर होस्टेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.वीडियो में दिख रहा है कि श्रद्धा और राहुल दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं. श्रद्धा उन्हें फोन में कुछ दिखा भी रही हैं. इस वीडियो को एयर होस्टेस ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. उसके बाद हर तरफ ये वीडियो वायरल हो गया है.

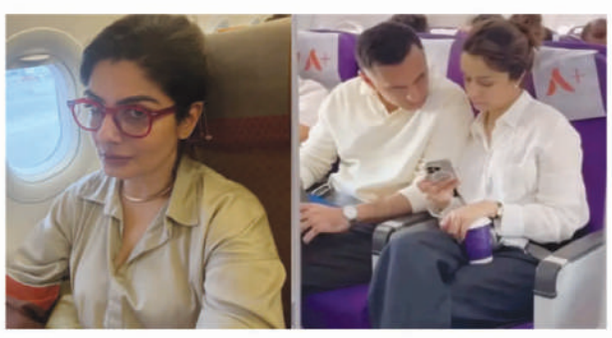

रवीना टंडन ने क्या कहा ?

जैसे ही ये वीडियो रवीना टंडन ने देखा, वो उस एयर होस्टेस पर भड़क उठीं. वो इसलिए गुस्सा हो गईं, क्योंकि श्रद्धा को पता नहीं था कि उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है. ऐसे में ये किसी की प्राइवेसी में दखल देना है. रवीना ने लिखा, ये प्रावेसी का उल्लंघन है. क्रू को ऐसा करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसा करने से पहले पूछना जरूरी है. क्रू मेंबर्स से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की जाती.अब रवीना टंडन का ये रिएक्शन वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग भी लिख रहे हैं कि एयर होस्टेस को वीडियो नहीं बनाना चाहिए. बहरहाल, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों ने अपने रिश्ते पर कभी पब्लिकली तौर पर बात तो नहीं की, लेकिन अक्सर दोनों को एक साथ देखा जाता है.

श्रद्धा कपूर का डांस वीडियो

हाल ही में श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो दिल पर चलाई छुरियां गाने पर डांस करती दिखीं. श्रद्धा के इस वीडियो में भी राहुल मोदी की झलक देखने को मिली है. इस वजह से भी दोनों सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं.

न्यूज फ्लैश

भाजपा नेता लोगों तक पहुंचा रहे राहत सामग्री उसकी करते हैं सराहना

दिव्य दिल्ली : सुमित (हमीरपुर)

बड़सर कांग्रेस नेता राजेश बन्याल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को राहत सामग्री भेज रही है। जिसकी वह सराहना करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। उसकी भरपाई इस तरह की मदद से नहीं होगी। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया है कि वह केंद्र के समक्ष हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाएं। राजेश वनियाल ने कहा कि बीते बस हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी उसके लिए भी केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज जारी नहीं किया गया था। अब इस वर्ष भी बरसात के शुरूआती दौर में मंडी और कल्लू तथा अन्य जिलों में काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान करोड़ों रुपए की मशीनरी और सड़कें और लोगों के घर आपदा में बह चुके हैं। उनकी मदद केवल आर्थिक पैकेज से ही की जा सकती है। उन्होंने भाजपा के नेताओं को चेताया कि वह केंद्र के समक्ष हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाएं और हिमाचल के लिए राहत पैकेज केंद्र सरकार से लेकर आए ताकि हिमाचल का फिर से विकास हो सके।

मंडी दौरे पर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए की गई घोषणाएं होंगी कारगर साबित, विवेक शर्मा

दिव्य दिल्ली : (ऊना /बंगाणा)

कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने बंगाणा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जिला मंडी दौरे के दौरान बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए एक के बाद एक राहत घोषणाएं कर न केवल जनभावनाओं का सम्मान किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि उनकी सरकार आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिन परिवारों के घर बाढ़ में बह गए या पूरी तरह से नष्ट हो गए, उन्हें सात लाख रुपये की राशि आशियाना निर्माण सहायता के रूप में देने की घोषणा की। साथ ही, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से भूमि प्रदान करने का भी वादा किया गया। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू की इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जो कहा उसे करके भी दिखाया है। विवेक शर्मा ने कहा कि बीते अढ़ाई वर्षों से लगातार प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हो रहे परिवारों को राहत प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और मुख्यमंत्री द्वारा मंडी में की गई घोषणाएं इसी का प्रमाण हैं।

जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, पठानकोट की जिला प्रशासनिक परिसर मलिकपुर में त्रैमासिक बैठक आयोजित

रंधावा (पठानकोट)

आज जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, पठानकोट की जिला प्रशासनिक परिसर मलिकपुर में त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता श्री एस.एस. सैनी, जिला कल्याण अधिकारी, पठानकोट ने की। बैठक में श्री पवन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर सर्वश्री सुमन कुमार, सचिव नगर निगम पठानकोट, कर्नल हरमिंदर सिंह, 21 सब एरिया, पठानकोट, दविंदर सिंह, पंचायत अधिकारी, मनजीत सिंह, डी.जी. सिंह, उप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अमनदीप कुमार, उप जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, तेजविंदर सिंह, जिला रोजगार अधिकारी, पठानकोट, राम लुभाया, जिला जनसंपर्क अधिकारी, पठानकोट सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।मीटिंग के दौरान जानकारी देते हुए श्री एस.एस.सैनी जिला कल्याण अधिकारी पठानकोट ने बताया कि यह विभाग पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए काम करता है। पूर्व सैनिकों की पुनः नियुक्ति का उद्देश्य उनके नाम दर्ज करना और उनकी मांग के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को उनके नाम भेजना शामिल है।

शाहपुर कंडी पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

समता योग आश्रम की ओर से शाहपुर कंडी में उनके पावन तप स्थान पर कुछेक लोगों की ओर से उनके धार्मिक ग्रंथ के छेड़छाड़ करने व फाडने के आरोप में तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पांच आरोपियों के खिलाफ बेअदवी का मामला दर्ज किया है। समता योग आश्रम ने बताया कि उक्त आरोपियों की ओर से सोची समझी साजिश के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके लिए शाहपुर कंडी पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत पर , पांच लोगों पर , बीएनएस की धारा 291,351(3), 324, 61(2)के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत अनुसार रवि गोयल पुत्र धर्मपाल गोयल निवासी अंबाला सिटी हाल निवासी समता योग आश्रम माधोपुर कैंट ने बताया के 23 जून को वह तरेहटी आदर्श नगर नजदीक रावि सदन में अपने आश्रम की जमीन पर, जहां सतगुरु देव महात्मा मंगत राम जी का सत्संग करवाया जा रहा था।

मार्च 2024 में रिटायर हुए परिवहन कर्मचारियों को आज दिन तक ना आर्थिक लाभ हुआ ना पेंशन मिली'

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारी जून 2025 की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तथा उन्हें अपना जीवन यापन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ' आज कंडवाल के समीप नागिनी में आयोजित परिवहन निगम पेंशनर संगठन की बैठक में संगठन के धर्मशाला नगरोटा वगबा पठानकोट जसूर यूनिटों से आऐ पूर्व परिवहन कर्मचारियों ने सरकार कि इस मुद्दे पर कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि वह इसके विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए विवस हो जाएंगे' बैठक में सरकार को इस बात के लिए भी आडे हाथों लिया गया कि मार्च 2024 में रिटायर हुए निगम कर्मचारियों को पेंशन तो क्या मिलनी थी.उनके मिलने वाले सारे आर्थिक लाभ आज दिन तक नहीं मिले हैं' प्रदेश के विधायकों में मंत्रियों की वेतन बढ़ोतरी तो तुरंत लागू कर दी जाती है और गरीब कर्मचारियों का हक सरकार मार रही है

कांगड़ा पुलिस द्वारा नकली सोना बेचने वालों पर की गई कार्रवाई: एसएसपी कांगड़ा शालिनी

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर एस एस पी जिला कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने आज धर्मशाला में मीडिया को नकली सोना बेचने वालों पर कार्यवाही की जानकारी दी है ' उन्होंने लोगों को कहा कि इस मामले में जागरूक रहें ' हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा एस एस पी शालिनी अग्निहोत्री आज के दौर में नशा माफिया भू माफिया शराब माफिया बन माफिया अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने में जिला कांगड़ा में काफी कामयाब हुई है'

भारत पेट्रोलियम द्वारा कठुआ ट्रक यूनियन में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा "स्वच्छता पखवाड़ा" के अंतर्गत आज कठुआ ट्रक यूनियन परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूनियन अध्यक्ष श्री भूपिंदर सिंह, उपाध्यक्ष श्री मोहिंदर सिंह, अन्य पदाधिकारीगण तथा लगभग 160 ट्रक ड्राइवरों व ट्रांसपोर्ट ऑनर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरूआत स्वच्छता के प्रति जागरूकता वार्ता से की गई, जिसमें उपस्थित सभी को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसके उपरांत उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता शपथ ली गई।भारत पेट्रोलियम की ओर से ट्रक यूनियन परिसर में यात्रियों एवं सदस्यों की सुविधा हेतु दो बेंच भेंट स्वरूप प्रदान की गईं और उन्हें यूनियन पार्क में स्थापित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई।

प्रताप वर्ल्ड स्कूल इंदौरा की प्रिंसिपल रेणु परमार को रविन्द्रनाथ टेगौर नैशनल प्रिंसिपल अवार्ड से किया गया सम्मानित

दिव्य दिल्ली : (अजय शर्मा) इन्दौरा

प्रताप वर्ल्ड स्कूल इंदौरा की प्रिंसिपल को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए रविन्द्रनाथ टेगौर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें पार्क प्लाजा चंडीगढ़ जीरकपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में टाकेसी ओगरा द्वारा प्रदान किया गया। प्रिंसिपल रेणु परमार ने पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक नवाचार किए हैं।

उनके नेतृत्व में स्कूल ने न केवल शैक्षणिक परिणामों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बल्कि सांस्कृतिक, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों में भी राज्य स्तर पर कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं।स्कूल कि एमडृ डी डृ डॉडृ रिचा महाजन ने बताया कि स्कूल के अध्यापकों , छात्रों , अभिभावकों और स्थानीय समुदाय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जताई है।

स्कूल में इस अवसर पर विशेष सभा आयोजित की गई, जहाँ छात्रों और शिक्षकों ने प्रिंसिपल का स्वागत किया।इस अवसर पर प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेणु परमार ने कहा,कि "यह सम्मान केवल मेरा नहीं, पूरे विद्यालय परिवार का है। मैं सभी शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों का धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से यह संभव हुआ।"

विजय मेमोरियल स्कूल इंदौरा में प्रथम जिला स्विमिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन

दिव्य दिल्ली : अजय शर्मा (इन्दौरा)

कांगड़ा जिला स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा विजय मेमोरियल स्कूल इंदौरा में प्रथम जिला स्विमिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। चैंपियनशिप की अध्यक्षता विजय मेमोरियल स्कूल इंदौरा के डायरेक्टर इंजीनियर सचिन शर्मा ने की। जबकि बतौर मुख्यअतिथि हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के राज्य महासचिव इशान अख्तर एवं राज्य उपाध्यक्ष राकेश बलिया ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। हिमाचली परंपरा अनुसार विजय मेमोरियल स्कूल इंदौरा के डायरेक्टर इंजीनियर सचिन शर्मा एवं अशोक प्रधानाचार्य सोनिया शर्मा ने मुख्य अतिथि राज्य महासचिव इशान अख्तर एवं राज्य उपाध्यक्ष राकेश बलिया को हिमाचली टोपी शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के राज्य महासचिव इशान अख्तर ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं। खेल हमें अनुशासन, संघर्ष, और टीमवर्क की भावना सिखाते हैं।खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मक को बढ़ावा देता है ।

आईटी 2.0 एप्लिकेशन का रोलआउट– डिजिटल परिवर्तन पहल

प्रेम स्वरूप शर्मा (नगरोटा सूरियां)

भारत सरकार के डाक विभाग को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अगली पीढ़ी का एपीटी एप्लिकेशन रोलआउट किया जा रहा है, जो हमारे डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस परिवर्तनात्मक पहल के तहत, उन्नत प्रणाली 15.07.2025 से देहरा, बनखंडी , हरिपुर, कस्बा कोटला, चनौर, ज्वालामुखी, रक्कड़, डाडासिब्बा, खुंडियां, संसारपुर टेरेस, ढलियारा, कोहाला, थिल, गरली, मुहल, ठोर, घल्लौर, नेहरन पुखर, टीहरी, घमरूर, पीरसलूही, टिपरी, गुलेर, प्रागपुर के डाकघरों में लागू की जाएगी।इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए 14.07.2025 को एक नियोजित डाउनटाइम निर्धारित किया गया है। 14.07.2025 को डाकघरों में कोई भी सार्वजनिक लेन-देन नहीं किया जाएगा। यह अस्थायी सेवा निलंबन डेटा माइग्रेशन, प्रणाली सत्यापन और कॉनफि गरेशन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, ताकि नया सिस्टम सही और प्रभावी ढंग से लाइव हो सके।

आईटीआई सोलन में रैंप ए हुनर 2025 का पहली बार किया गया आयोजन

दिव्य दिल्ली : (सोलन)

आईटीआई सोलन में युवाओं की प्रतिभा को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से रैंप ए हुनर 2025 का आयोजन हिमाचल में पहली बार किया गया । जिसमें रैंप वॉक का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष भर में छात्रों द्वारा खुद के बनाए परिधानों में छात्राओं ने रैंप पर जलवा बखेरा । वही सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित छात्रों द्वारा बनाए गए कपडो को प्रदर्शित भी किया गया ।आईटीआई सोलन के प्रधानाचार्य ललित कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार व निदेशालय के आदेशानुसार बच्चों के मनोबल को बढाने के लिए रैंप ए हुनर 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दूसरे दिन भी विकास खंड अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की उड़ाई धज्जियाँ

दिव्य दिल्ली : प्रेम स्वरूप शर्मा (नगरोटा सूरियां)

दूसरे दिन भी विकास खंड कार्यालय नगरोटा सुरियाँ के सभी कमरों पर ताले लटके रहे, हालांकि इसकी सूचना पिछले कल सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जिलाधीश काँगड़ा, निदेशक ग्रामीण विकास विभाग तथा स्थानीय पुलिस चोंकि नगरोटा सुरियाँ को दे दी गई थी, संघर्ष समिति के सयोंजक संजय महाजन ने बताया की अभी तक चुनाव से संवधित फाईले तथा पूरी की पूरी चुनाव सामग्री, कम्प्यूटर, प्रिंटर, आधे से ज्यादा फर्नीचर, लगभग दो ट्रक सामान नगरोटा सुरियाँ कार्यालय में पड़ा है,

महाजन ने कहा की क्यूंकि अब अधिसूचना पर स्टे है तो अब यह सामान जब तक अदालत का निर्णय नहीं आ जाता इसको कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ से चोरी से उठाने का प्रयास या दुःसाहस न करे, इस विकास खंड पर संघर्ष समिति सदस्यों की 24 घंटे नजर रहेगी, उधर धीरज अत्तरी, जसवंत सिंह तथा गुरचरण बेदी ने प्रशासन तथा पुलिस से अपील की है की है की जब तक माननीय न्यायलय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक इस सामान को कोई भी शरारती तत्व इसको नुकसान न पहुंचाए और न ही इसे यहाँ से ज्वाली शिफ्ट करने की कोशिश करे, यदि कोई भी इस सामान से छेड़ छाड़ करेगा तो इस सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, इस मोके पर स्पेल के उप प्रधान विक्रम चावला, वार्ड पंच पंकज कुमार, अंशुल शर्मा, जोगिंदर सिंह, कुलभूषण शर्मा, उपस्थित थे

जीएसटी अनुपालन और राजस्व वृद्धि पर विशेष अभियान,नूरपुर के बोड़ में हुआ गोष्ठी का आयोजन

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा आज राजस्व जिला नूरपुर में जीएसटी अनुपालन और राजस्व वृद्धि विषय पर जसूर के समीप बोड़ स्तिथ मैपल फार्म में सुबह एक गोष्ठी का आयोजन किया । कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिभाग उत्तर जीएसटी जोन पालमपुर राकेश भारतीय विशेष रूप से मौजूद रहे।इस अभियान के तहत मुख्य रूप से जीएसटी इनवॉइसिंग के प्रति जागरूकता, ह्लजागो ग्राहक जागोह्व पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जीएसटीआईएन का अनिवार्य प्रदर्शन, जीएसटी रिटर्न की नियमित फाइलिंग तथा 50,000 से अधिक के माल के लिए ई-वे बिल का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।नूरपुर व्यापार मंडल प्रधान अश्विनी सूरी व जसूर व्यापार मंडल के प्रधान राजू महाजन, सहित नूरपुर व जसूर के व्यापारी,अकाउंटेंट, सीए सहित अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीएसटी सम्बंधित समस्याओं की चर्चा व निदान के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।वही विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों और आम नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर जीएसटी नियमों का पालन करने की अपील की ताकि प्रदेश में राजस्व संग्रह को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

लाहौल विधायक अनुराधा ने किया नालडा पंचायत का दौरा

दिव्य दिल्ली : रंजीत लाहौली (केलांग)

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने बुधवार से लाहौल घाटी के दौरे पर पहुंची। उन्होंने छह दिवसीय दौरे का आगाज किया । नालडा पंचायत के खेतों में सड़क निकालने पर स्थानीय लोगों ने विधायक अनुराधा राणा के धन्यवाद किया। वहीं लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा छह दिवसीय दौरे पर लोगों से मिलेंगी । और लोगों की समस्याओं को सुना और दूर करने की आश्वासन दिया। । और पुल के काम को तेजी लाने को लोक निर्माण विभाग को कहा ।साथ में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कोठी ,रपडिंग,जाहलमा,हां लिंग एवं जसरथ आदि गांवों में किए गए सिंचाई कूहल के कार्य एवं अन्य तटीकरण के कार्यों तथा पिछली बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए कुहलों एवं आमजन के हो रहे भूमि कटाव के नुकसान का जायजा लिया । प्रशासन एवं विभागों को नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए । सिंचाई कुहलों को बहुत जल्द दुरस्त किया जाएगा । और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा । विधायक अनुराधा राणा ने लोगों की समस्याओं को सुनीं। उनके साथ जिप अध्यक्ष वीना देवी,जिप सदस्य छेजंग डोलमा बीडीओ डाक्टर विवेक गुलेरिया, तहसीलदार रमेश राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे ।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397